रायपुर, वर्ष-18, अंक- 6, जून 2022, मूल्य ₹ 10

दीप कमल

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भाजपा द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में हुई आयोजनों में सभी भाजपाजनों ने उत्साह से भाग लिया।

दीप कमल

संपादक
सुभाष राव

कार्यकारी संपादक
पंकज कुमार झा

मुद्रक एवं प्रकाशक **विष्णुदेव साय** द्वारा, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, के लिए **मूणत ऑफसेट प्रिंटर्स** रायपुर से मुद्रित एवं एकात्म परिसर, रजबंधा मैदान रायपुर से प्रकाशित।

स्वत्वाधिकारी
भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़

ई-मेल
jay7feb@gmail.com

फोन
0771-2233500, 4266000

सोशल मीडिया से

Narendra Modi
★ Favourites · 11 h ·

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों, दलितों के साथ-साथ हाशिए पर लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका उत्कृष्ट कार्यकाल था। मुझे विश्वास है कि वह हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी।

लाखों लोग, विशेष रूप से जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और कठिनाइयों का सामना किया है, श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी के जीवन से बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव हमारे देश को बहुत लाभ पहुंचाएगा।

Smriti Z Irani
@smritiirani

आज, @BJP4CGState प्रदेश कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय @drramansingh जी की उपस्थिति में महिला मोर्चा की बहनों के साथ बैठक की।

भाजपा सरकार के #8YearsOfSeva कार्यकाल में लोककल्याण और विकास संबंधित उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित है।

Translate Tweet

Dr Raman Singh
29 m ·

...और कितना गिरेंगे भूपेश बघेल!

इतना दुर्बल मुख्यमंत्री नहीं देखा, जो सच नहीं देख सकता।

ओपी चौधरी ने आपके लचर प्रशासन की खामियां उजागर की तो गैरजमानती धाराएं लगा दीं।

हम डरने वाले नहीं हैं, सनद रहे, यह तानाशाही नहीं चलेगी, ईंट से ईंट बजा देंगे कांग्रेस सरकार की।

पूर्व आईएएस ओपी चौधरी पर एफआईआर

कोयला चोरी के अपलोड वीडियों का मामला

कोरबा. ट्विटर एकाउंट में कोयला चोरी के अपलोड वीडियों के मामले में पुलिस ने पूर्व आईएएस व भाजपा नेता ओपी चौधरी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है. वायरल वीडियो को कोरबा के

Vishnu Deo Sai
9 h ·

जनजातीय समाज के विकास में अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पण करने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मदीवार घोषित करने का निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ । श्रीमती मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होगा।

अंदर के पन्नों में

विशेष संपादकीय	04
एक भारत, श्रेष्ठ भारत	05
कार्य समिति बैठक	07
राजनीतिक प्रस्ताव	10
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण	12
ईडी के शिकंजे में कांग्रेस आलाकमान	19
समाचार कमल	21
राज्यसभा और छत्तीसगढ़ियावाद	29

अमित शाह

भगवान शंकर की तरह विषपान करते रहे मोदी

2002 गुजरात दंगों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा समाचार एजेंसी ANI को दिए साक्षात्कार का अंश ही 'दीप कमल' के इस अंक का संपादकीय है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 18 साल से विषपान करते रहे। मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ आ रहा है, तो अब आनंद आ रहा है। भाजपा विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ विचारधारा के लिए राजनीति में आए पत्रकार और एनजीओ ने मिलकर आरोपों का इतना प्रचार किया और इसका इकोसिस्टम इतना मजबूत था कि लोग इनको ही सत्य मानने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम करती थी। एनजीओ ने कई पीड़ितों के हलफनामे पर हस्ताक्षर किए और उन्हें पता भी नहीं है। सब जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ ये सब कर रही थी। उस समय की यूपीए की सरकार ने एनजीओ की बहुत मदद की है। गुजरात में हमारी सरकार थी लेकिन यूपीए की सरकार ने एनजीओ की मदद की है। सब जानते हैं कि ये केवल मोदी जी की छवि खराब करने के लिए किया गया था।

जहां तक गुजरात दंगों में सेना को नहीं बुलाने का सवाल है, तो हमने कोई लेटलतीफी नहीं की। जिस दिन गुजरात बंद का एलान हुआ था उसी दिन हमने सेना को बुला लिया था। गुजरात सरकार ने एक दिन की भी देरी नहीं की थी और कोर्ट ने भी इसका प्रोत्साहन किया है। दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, जब इतने सारे सिख भाइयों को मार दिया गया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। ये लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं?

दंगे होने का मुख्य कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 16 दिन की बच्ची को उसकी मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है और मेरे हाथ से मैंने अंतिम संस्कार किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रेन में आग लगने के बाद की घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं बल्कि स्वप्रेरित थी और तहलका द्वारा स्टिंग ऑपरेशन को भी खारिज कर दिया क्योंकि इसके आगे-पीछे का जब फुटेज आया तब पता चला कि ये स्टिंग राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था।

तीन जजों की बेंच ने मामले को दोबारा शुरू करने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच के दौरान जो भी सबूत मिले, उनसे मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक हिंसा भड़काने के लिए 'सर्वोच्च स्तर पर आपराधिक षड्यंत्र रचने संबंधी कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है।' अदालत ने कहा, 'अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर करके राज्य भर में सामूहिक हिंसा का कारण बनने के लिए आपराधिक साजिश रचने में नामित व्यक्तियों की संलिप्तता को लेकर स्पष्ट और प्रत्यक्ष सामग्री का अभाव है।'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 2006 से कार्यवाही चल रही है... इसमें शामिल हर पदाधिकारी की ईमानदारी पर सवाल खड़े करने की हिमाकत हुई ताकि गुप्त उद्देश्य के लिए मामले को गरमाये रखा जा सके।' अदालत ने कहा कि जो प्रक्रिया का इस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कठघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की जानी चाहिए।'

नैशनल हेराल्ड मामले में राहुल से प्रवर्तन निदेशालय ने 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है। विरोध में कांग्रेसियों ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किए। जबकि मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी लेकिन तब किसी ने धरना-प्रदर्शन नहीं किया था और हमने कानून को सहयोग दिया और मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी लेकिन कोई भी धरना-प्रदर्शन नहीं हुआ था। जहां तक दंगों का सवाल है तो आप 5 साल बीजेपी और कांग्रेस के शासन काल की तुलना करें तो पता चल जाएगा कि किसके शासन में अधिक दंगे हुए।

मोदी और भाजपा के खिलाफ करीब दो दशक से दुष्प्रचार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। जिन लोगों ने मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्हें मोदी जी और बीजेपी से माफी मांगनी चाहिए।

●●●

प्रतिक्रिया कृपया इस आईडी पर दें-
jay7feb@gmail.com

शिवप्रकाश

डॉ. मुखर्जी के सपनों का एक भारत, श्रेष्ठ भारत

जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के दायरे में लाने और एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान (झंडा) के विरोध में सबसे पहले आवाज उठाने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 23 जून को बलिदान दिवस है। उनका यह स्वप्न स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बाद तब पूरा हुआ जब हम सबके प्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगस्त 2019 में संसद में संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35-A को समाप्त करने का बिल पारित कराया। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर भारत देश का सही मायनों में अभिन्न अंग बना। विशेष राज्य का दर्जा, अलग संविधान, देश के अन्य प्रदेशों के नागरिकों के जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता जैसी जिन शर्तों और नियमों के साथ जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था, डॉ. मुखर्जी प्रारंभ से ही उसके विरोध में थे। उन्होंने इसके लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर जाकर अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन चाहकर भी उनका यह स्वप्न उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया और रहस्यमय परिस्थितियों में 23 जून 1953 को उनकी मृत्यु हो गई।

डॉ. मुखर्जी को जम्मू कश्मीर एवं देश की अखंडता के लिए बलिदान देने वाले पहले व्यक्ति के तौर पर जाना गया। इसीलिए देश उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाता है।

भारतीय संविधान के दायरे में आने के बाद से जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकारों ने प्रदेश में कृत्रिम सामान्यता बनाये रखी। वास्तविक अर्थों में जम्मू कश्मीर की स्थिति अनुच्छेद 370 के प्रावधानों की समाप्ति के बाद ही सामान्य हुई है। अब जम्मू कश्मीर का सही मायनों में विकास संभव होगा। केंद्र की भाजपा सरकार ने भी राज्य के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट संसद से पारित कराया है जिससे जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य पिछले वर्षों के मुक़ाबले ज्यादा तेजी से पूरे किये जा सकेंगे। राज्य में अब न केवल रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं बल्कि उद्योग जगत मे निवेश के लिए भी उत्साह दिखा रहा है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों की समाप्ति के बाद प्रदेश में अब केंद्र के क़रीब 890 क़ानून लागू हो गए हैं। यही नहीं अब प्रदेश के लोग संविधान के तहत मिलने वाले आरक्षण के भी हक़दार हो गए हैं जिनसे उनके लिए विकास और समृद्धि के रास्ते खुले हैं। पर्यटकों की संख्या मे वृद्धि हुई है। पंचायतों को सीधे 2200 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओ के विकास के लिए 2 नए एम्स, 6 नए मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर संस्थान एवं 15 नर्सिंग कौलेज पर कार्य चल रहा है। युवा, पुलिस एवं अन्य संस्थानों मे रोजगार प्राप्त कर रहे है।

यूं तो डॉ. मुखर्जी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही भारत विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने संविधान सभा की बैठकों में भी अपने विचारों को काफी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर कांग्रेस नेताओं और तत्कालीन सरकार की सोच के साथ वे कभी एकमत नहीं थे। वे पहले ही दिन से जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान की सीमाओं के अंतर्गत लाने के पक्षधर थे। इसे संघर्ष की सीमा तक ले जाने की शुरुआत अप्रैल 1952 में तब हुई जब जम्मू कश्मीर की प्रजा परिषद पार्टी के नेता पं. प्रेमनाथ डोगरा नई दिल्ली में उनसे मुलाकात करने आए। डोगरा ने डॉ. मुखर्जी से राज्य में चल रहे इस आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया। डॉ. मुखर्जी ने डोगरा को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से मिलकर अपना पक्ष रखने को कहा। लेकिन इसे विडंबना कहें या कांग्रेस की तत्कालीन सरकार का अड़ियल रवैया, डोगरा को अपनी बात रखने के लिए नेहरू से समय ही नहीं मिला।

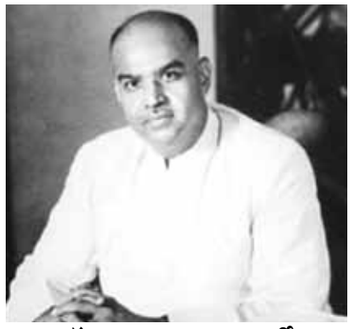

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
6 जुलाई 1901 - 23 जून 1953

डॉ. मुखर्जी अपने सिद्धांतों को लेकर अटल थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर अपने विचारों पर कभी समझौता नहीं किया और प्रजा परिषद पार्टी के बुलावे पर अगस्त 1952 में वह जम्मू में एक सभा में शामिल हुए और 'एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे' का नारा दिया। डॉ. मुखर्जी को केवल

जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान लागू करने की नीति के समर्थक के तौर पर ही नहीं देखा जाना चाहिए। शिक्षा, समाज, संस्कृति और राजनीति में भी उनका योगदान बेहद उल्लेखनीय रहा है। उनकी राजनीतिक यात्रा कलकत्ता विश्वविद्यालय क्षेत्र से 1929 में विधान परिषद से प्रारंभ हुई। बंगाल के हितों की रक्षा के लिए वे फजलुल सरकार में वित्त मंत्री रहे। भारत सरकार के उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने 6 अप्रैल 1948 को उद्योग नीति लायी। तीन भागों में उद्योगों का विभाजन कर भारत में उद्योगों का विकास उनका प्रयास था। औद्योगिक वित्त विकास निगम की स्थापना, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, चितरंजन रेलवे कारखाना, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना सभी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प के साकार रूप है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु जी के विभाजन के समय, पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान पर विफल नीति के विरोध में उद्योग मंत्री से त्यागपत्र देकर वे भारत में आए लाखों शरणार्थियों की सेवा में जुट गए। हमें कांग्रेस के राष्ट्रवादी विकल्प की आवश्यकता है, इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। डॉ. श्यामा प्रसाद जी जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष बने। प्रथम लोकसभा चुनाव मे साउथ कोलकाता से सांसद सदस्य भी चुने गए।

वर्ष 1934 से 1938 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति होने का श्रेय भी उनके ही नाम है। इसी पद पर उन्होंने दो कार्यकाल रहते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय को प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ब्रिटिश इंडिया के प्रतीक 'ब्रिटिश मोहर' को बदलकर उस स्थान पर 'खिलते हुए कमल में श्री अंकित' कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह बनाया। उनकी शिक्षा दृष्टि उनके ही शब्दों में "मैं ऐसे व्यक्ति बनाना चाहता हूं जो नए बंगाल के योग्य नेता बने।" इसी उद्देश्य से उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अनेक नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए।

साल 1943 में आए भीषण अकाल में सरकार के निकम्मे एवं द्वेषपूर्ण व्यवहार को समाज के सामने लाते हुए स्वयं सेवा के मैदान में उतर गए। बंगाल रिलीफ कमेटी बनाकर, साथ ही तत्कालीन अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं को उन्होंने साथ लेकर यह सेवा कार्य किया। मुफ्त रसोई,

भारत के पहले कैबिनेट के दो गैरकांग्रेसी मंत्री डॉ. मुखर्जी और डॉ. अम्बेडकर।

निशुल्क अनाज वितरण, सस्ती कैंटीन, अनाज की दुकाने, आवास, वृद्धों एवं बच्चों के लिए दूध एवं दवाइयां वितरण कमेटी के द्वारा हुआ। देश के विभाजन की त्रासदी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी आंखों से देखा था। बंगाल के कलकत्ता, नोआखाली सहित अनेक स्थानों के दंगो में मानवता कराह उठी थी। ग्रेट कलकत्ता के नाम से कुख्यात नरसंहार आज भी लोगों में सिहरन पैदा करता है। समाज का मनोबल बढ़ाने, उचित मार्गदर्शन करने एवं पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने सभी स्थानों का प्रवास किया। भारत के विभाजन के घोर विरोधी होने के बाद भी जब उनको लगा कि यदि हमने बंगाल के विभाजन की बात नहीं की तब संपूर्ण बंगाल ही हमारे हाथ से चला जाएगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे भारतीय नेताओं के साथ-साथ अंग्रेज अधिकारियों से भी मिले। आज के भारत में, बंगाल उन्हीं के संकल्प का परिणाम है। उनको नव बंगाल का 'शिल्पी' भी कहा जाता है। एकजुट भारत की उनकी इस सोच पर आगे कदम बढ़ाने में हमें 70 वर्ष से भी अधिक का समय लग गया। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉ. मुखर्जी की इस सोच को वास्तविकता में बदल रही है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत के नारे के माध्यम से मोदी सरकार देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अंतर्गत लाने के दो वर्ष पूरे होने को हैं। मोदी सरकार की नीतियों में डॉ. मुखर्जी की आकांक्षाओं की झलक स्पष्ट देखी जा सकती है। नई शिक्षा नीति को लागू करना डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शिक्षा अभिव्यक्ति ही है। वह दिन दूर नहीं जब भारतीय जनसंघ, जिसने बाद में भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप लिया, के संस्थापक डॉ. मुखर्जी की राष्ट्रीय एकता व अखंडता की भावना सशक्त होकर भारत को विश्व के श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं) ●●●

भाजपा की प्रदेश कार्य समिति बैठक

भाजपा सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है: डी पुरंदेश्वरी

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ परिसर में प्रदेश कार्यसमिति को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी ने कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल कार्यकाल का 8वां वर्ष पूरा हो रहा है। भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव में *सबका साथ-सबका विकास* के नारे के साथ जनता के बीच गई थी एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने हमें पुनः अपना समर्थन दिया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता का पूर्ण समर्थन हमें मिलेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए हम अभी से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की चुनौती में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर से बाहर निकलकर सेवा किया वहीं अन्य राजनैतिक दल अपने-अपने घरों में रहे। यही भाजपा को अन्य राजनीतिक दलों से अलग बनाता है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व के आहवान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा जनता के बीच सेवा भाव के साथ जाएंगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम तेजी से विकास कि ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार एवं जानदार 8 साल 30 मई को पूरा हो रहा है। देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में भाजपा ने पुनः सरकार बनाई है। वहां की जनता का प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने पुनः विश्वास प्राप्त किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पंजाब से विदाई हुई साथ ही यूपी में 380 सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। उन्होंने कहा कि 2023 में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। विधानसभा चुनाव के दौरान 36 घोषणा कर सत्ता में आई कांग्रेस साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है और अपने खिलाफ हो रहे विरोध को सहन नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा

प्रदेश में लूट, डकैती, अपहरण उद्योग का रूप ले लिया है : विष्णुदेव साय

प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कार्यशैली से विश्वपटल पर देश को गौरवान्वित किया: डॉ. रमन

कि कांग्रेस ने गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी का वादा किया था, मंडी टैक्स हटाने का वादा किया था, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था लेकिन सत्ता पाने के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वादों से निभाने से मुकर गई है। प्रदेश के किसान व बेरोजगार युवा लगातार आत्महत्या कर रहे है। प्रदेश में लूट, डकैती, अपहरण, उद्योग का रूप ले लिया है। कांग्रेस पार्टी से लड़कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और हम 2023 में निश्चित ही विशाल जनमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएंगे।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने समापन उद्बोधन में कहा कि बूथों को मजबूत करने का माइक्रो लेवल का कार्यक्रम करना है। आप जितनी गंभीरता से काम करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आयेगा कार्य विस्तार योजना प्रमाणिकता का काम है, गुजरात में सबसे पहले यह कार्य सफलतापूर्वक किया जा चुका है और पूरे देश में यह कार्य किया

जा रहा है। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष पूर्ण होंगे। पिछले 8 वर्षों में संतुलित विकास से देश में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। सन् 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में परिवारवाद, सिफारिश युग का खात्मा हुआ। भाजपा का मतलब राष्ट्र प्रथम, देशहित से समझौता नही, भाजपा का मतलब पारदर्शिता के साथ गुड गवर्नेंस व योग्यता को अवसर भाजपा का मतलब सनातन की रक्षा व महापुरुषों का सम्मान। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल के शासन में कितनी आर्थिक व राजनीतिक विपत्तियां आयी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशल नेतृत्व व सूझबूझ से इन विपत्तियों से मुकाबला किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुशासन व सेवा को अपनाकर बताया कि भाजपा अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग कैसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यशैली से विश्वपटल पर देश को गौरवान्वित किया।

भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय ने संगठनात्मक वृत प्रस्तुत करते हुए 1 से 15 जून तक चलने वाले सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजना के प्रभारियों को दायित्व सौंपा। उन्होंने कहा कि दशकों पहले जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तब की संकल्पना राम मंदिर निर्माण, व धारा 370 समापन अब जा कर पूर्ण हुआ। केन्द्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यों को जनता तक रिपोर्ट कार्ड के रूप में बताएं। उन्होंने केन्द्र सरकार की 8वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रमों की जानकारी दी। ●●●

कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा

हाल में विधानसभा के चुनावों में चार राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर यह कार्यसमितिमतदाताओं का आभार व्यक्त करती है।यह जनादेश वास्तव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सतत बढ़ती लोकप्रियता का अनुपम प्रकटीकरण है।मोदी जी ने अपने कार्यकाल के ऐतिहासिक 8 वर्ष पूरा किये हैं, इस अवसर पर भी यह कार्यसमिति अपने महानायक और प्रखर नेता का अभिनंदन करती है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत आज कृषि समेत तमाम मामलों लगातार इतिहास रच रहा है।

प्रस्तावः श्री नारायण चंदेल, प्रदेश महामंत्री

जहां युद्ध और अन्य वैश्विक संकटोंके कारण विश्व के अनेक विकसित देश भी आज खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, वहां भारत की शानदार खाद्य सुरक्षा हम सबके लिए संतोष और गर्व का विषय है।जहां दुनिया भर में आज उर्वरकों की कीमत आसामन पर है, वहां भारत में मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों से हज़ार रूपये से भी अधिक प्रति बोरे का अनुदान देकर खाद की कीमतों में बढ़ोत्तरी को रोका हुआ है।एक तरफ जहां मोदी जी की सरकार ने अनेक प्रयत्नों के बाद उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखा हुआ है वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार खाद की कालाबाजारी करा रही है। खाद को समितियों से गायब कर यूरिया 266 के बदले 600-700 में तो डीएपी 1200 के बदले 1800-2000 में बेचकर शासकीय संरक्षण में मुनाफाखोरी की जा रही है। इसी तरह दो रूपये किलो में गोबर खरीद उसे पांच गुना अधिक कीमत परकिसानों को वापस बेच देने, गुणवत्ता विहीन कथित वर्मी कम्पोस्ट के नाम परकम वजन के साथ मिट्टी-गिट्टी आदि मिला कर खाद खरीदने को बाध्य कर कांग्रेस वास्तव में फिरंगियों से भी अधिक गिरी हुई हरकत कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़
प्रदेश कार्यसमिति
राजनीतिक प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ में राज्य की भूपेश सरकार की वादाखिलाफी एवं उपेक्षा पूर्ण रवैय्ये के चलते किसानों में गहरा असंतोष है।प्रदेश में लाखों किसान कर्ज माफी से वंचित हुए हैं। वे बारदाना और खाद के लिए भटक रहे हैं। गुणवत्ता विहीन कीटनाशक, खाद के प्रयोग से नुकसान होने एवं रकबा के अनुरूप धान नही बिकने से परेशान किसान आत्महत्या करने मजबूर हुए हैं। शासकीय आंकड़ों के अनुसार ही प्रदेश में इस कांग्रेस शासन के दौरान 572 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है।इसके अलावा 9,281 युवाओं को भी आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा है।छत्तीसगढ़ के इन माटी पुत्रों को कोई अनुग्रह राशि भी नहीं दी गयी। प्रदेश में इस दौरान हत्या और बलात्कार के 10,231 मामले दर्ज किये गए हैं। क़ानून व्यवस्था प्रदेश में ऐसा बदहाल है।यहां धर्मांतरण का कारोबार भी किसी वायरस की तरह फ़ैलना घोर चिंताजनक है।

समर्थन : श्री केदार कश्यप, प्रदेश प्रवक्ता

विगत विधानसभा चुनाव में जारी कांगेस का कथित 'जन घोषणा पत्र' झूठ का पुलिंदाहै, यह बार-बार साबित हुआ है। प्रदेश का हर वर्ग आज ठगा और हताश महसूस कर रहा है। लाखों रोजगार का वादा, युवाओं कोबेरोजगारी भत्ता, किसानों को बोनस, शराबबंदी समेत तमाम वादों से कांग्रेस पूरी तरह से मुकर गयी है।

विगत विधानसभा चुनाव में जारी कांगेस का कथित 'जन घोषणा पत्र' झूठ का पुलिंदाहै, यह बार-बार साबित हुआ है। प्रदेश का हर वर्ग आज ठगा और हताश महसूस कर रहा है। लाखों रोजगार का वादा, युवाओं कोबेरोजगारी भत्ता, किसानों को बोनस, शराबबंदी समेत तमाम वादों से कांग्रेस पूरी तरह से मुकर गयी है। शिक्षक अभ्यर्थी,विद्या मितान,पुलिस अभ्यर्थी,बिजली कर्मचारी,कोरोना वारियर्स सभी अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं। हर वर्ग और समाज के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है। केंद्र की तरह महंगाई भत्ता देने की कर्मचारी संगठनों की उचित मांगों को भी यह सरकार दरकिनार कर रही है। केंद्र की तुलना में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का 12 प्रतिशत डीए हड़प लेना निहायत ही अनुचित कृत्य है।मोदी जी की सरकार ने वैश्विक परिस्थितियों के कारण बढ़ रही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत से राहत देने एक्साइज टैक्स में पुनः छूट दिया है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा जनता से मुनाफाखोरी करना जारी है, वैट में फिर भी राहत नहीं देने के प्रदेश कांग्रेस के जनविरोधी रवैया निंदनीय है। यह कार्यसमिति प्रदेश सरकार को वैट में अपेक्षित कमी करने और डीजल-पेट्रोल सेस ख़त्म करने की चेतावनी कांग्रेस सरकार को देती है।

प्रदेश भर के तमाम संगठन कांग्रेस की धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उन्हें अब आंदोलन से वंचित करने कांग्रेस ने एक आदेश निकला है जिसके कारण किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों का सरकार के खिलाफ अब कोई भी विरोध प्रदर्शन करना असंभव हो जाएगा।कांग्रेस सरकार द्वारा इस संबंध में 19 शर्तों के हलफनामे के साथ आयोजनों की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 'वाक् एवं अभिव्यक्ति' की स्वतन्त्रता का घोर उल्लंघन है।यह कांग्रेस का नया आपातकाल है। भाजपा लगातार इसको लेकर आंदोलनरत है, वह संविधान की इस हत्या का हर स्तर तक विरोध करने कटिबद्ध है।

कांग्रेस की समाज विरोधी सरकार ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दे परभी जिस तरह की स्तरहीन और दोमुहा राजनीति कर रही है, वह शर्मनाक है। हाई कोर्ट में इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश सरकार ने जानबूझ कर अपना पक्ष रखने में कमजोरी की। यहां तक कि ओबीसी आरक्षण रोकने के लिए हाईकोर्ट जाने वाले कार्यकर्ता को उपकृत भी किया। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस ने खुद आरक्षण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण देना ही नहीं चाहती है।

प्रदेश में आदिवासियों का जीना मुहाल है। पिछले तीन वर्ष में छत्तीसगढ़ में 25 हज़ार से अधिक आदिवासी बच्चों की चिकित्सा के अभाव में अकाल मृत्यु हुई है। 13 हज़ार से अधिक तो केवल नवजात शिशु इस दौरान अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, यह बहुत ही त्रासद स्थिति है। संरक्षित पंडो जनजाति के सैकड़ों लोगों की बीमारी और कुपोषण से असमय मौतहोते जाना एक बड़ी त्रासदी है।नक्सल इलाकों में फर्जी मुठभेड़ हो रही हैं, जिसमें अधिकतर आदिवासियों की ही जानें जा रही है। तेंदुपत्ता, आदिवासियों के जीवन-यापन का आधार रहा है। कांग्रेस सरकार ने उसकी खरीदी को भी लगभग ख़त्म कर दिया है, मात्र दो दिन उसकी खरीदी की गयी।

कोयला खदान के नाम पर हसदेव अरण्य को अपने स्वार्थवश उजाड़ने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। इन जंगलों के उजड़ने से प्रदेश के आदिवासी और किसानों के हितों पर, पर्यावरण पर अक्षम्य कुठाराघात होगा। हाथियों का कॉरिडोर लगभग ख़त्म होने से उसका प्रकोप भी बढ़ेगा। इससे पूरी तरह जन-जीवन असुरक्षित हो जाएगा।प्रदेश के रायगढ़, चिरमिरी, कोरबा आदि में कोल माफियाओं द्वारा संगठित रूप से सैकड़ों करोड़ के कोयले की चोरी की जा रही है,यह भी बिना शासकीय संरक्षण के संभव नहीं है।

दुर्भावना और ईर्ष्या के कारण भूपेश बघेल की सरकार न केवल केंद्र की जनहितकारी योजनाओं को रोक रही है बल्कि लागू हो रही योजनाओं में भयानक भ्रष्टाचार भी कर रही है।'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत मिले गरीबों के हिस्से के 25 सौ करोड़ से अधिक राशि का गबन भूपेश सरकार ने कर लिया है।'पीएम आवास' का घर रोक कर प्रदेश के 16 लाख से अधिक गरीबों का आशियाना छीनने का काम किया गया है।कांग्रेस सरकार लोगों साफ पानी तक मुहैया करा पाने में भी नकारा ही साबित हुई है। प्रदेशभर में 22 सौ स्थान आज भी ऐसे हैं, जहां निकायों ने स्वच्छ जल देने का काम ही शुरू नहीं किया है। 33 सौ करोड़ रुपए के केंद्र सरकार के 'जल जीवन मिशन' को भी कांग्रेस ख़त्म करने पर अमादा है। मोदी जी की सरकार जहां प्रदेश की करोड़ों जनता के लिए भोजन, आवास और साफ़ पानी की व्यवस्था कर रही है, वहां इन तमाम योजनाओं पर प्रदेश सरकार कुंडली मारकर बैठी है।

कोयला खदान के नाम पर हसदेव अरण्य को अपने स्वार्थवश उजाड़ने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। इन जंगलों के उजड़ने से प्रदेश के आदिवासी और किसानों के हितों पर, पर्यावरण पर अक्षम्य कुठाराघात होगा।

कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की मां-बहनों को भी बुरी तरह छला है। उसने महिला स्व सहायता समूहों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया। अपनी चहेती कम्पनी को लाभ पहुचाने के लिए 'रेडी टु ईट' का संचालन करने वाली 22 हजार बहनों का रोजगार छीन लिया। बुजुर्ग माताओं को वृद्धा-पेंशन नहीं दिया।शराबबंदी का वादा कर शराब की होम डिलीवरी शुरू की।छग सरकार ने कोरोना सेस भी लगाया लेकिन उसे भी 'कहीं अन्य' खर्च कर दिया।

भूपेश बघेल जी की कथित 'भेंट-मुलाक़ात' मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच सत्ता की लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। सारी मर्यादाएं तोड़ी जा रही है।दुःख की बात यह है कि प्रशासन के लोगों को और शासन के कर्मचारियों को भी इस लड़ाई का हिस्सा बना दिया गया है। कलक्टर-एसपी से सीएम के इशारे पर मंत्री के कार्यकम का बहिष्कार कराया जा रहा है, यह सबसे बदतर स्थिति है। समूचा प्रदेश कांग्रेस सरकार की वसूली से त्रस्त है, जबकि प्रदेश की कांग्रेस खुद अपने आलाकमान की वसूली से हलाकान है।

भाजपा की यह कार्यसमिति प्रदेश की जनता का आह्वान करती है कि छत्तीसगढ़ियों के मूंह से निवाला और साफ़ पानीतक छीन लेने वाली, उन्हें आवास तक से वंचित करने वाली, प्रदेश में लोकतंत्र को कुचल देने वाली तानाशाह, वसूलीबाज़, लबरा और भ्रष्ट भूपेश सरकार के खिलाफ जी-जान से संघर्ष करें।बाबा साहेब के संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे मौलिक अधिकारों तक को छीन लेने का मंसूबा रखने वाली कांग्रेस के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस शोषित छत्तीसगढ़ को मुक्त कराने का आह्वान यह कार्यसमिति करती है।

जय भारत - जय छत्तीसगढ़

सेवा और गरीब कल्याण के 8 वर्ष

जगत प्रकाश नड्डा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के आठ सफल वर्ष पूरे हो रहे हैं। आठ वर्षों की यह यात्रा जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के दंश से ग्रसित देश की राजनीति पर विकासवाद की जीत की अविरल यात्रा है। यह देश के लोकतंत्र को मजबूती देते हुए गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं एवं समाज में हाशिये पर खड़े हर व्यक्ति के सशक्तीकरण एवं उनके जीवन में उत्थान लाने की यात्रा है। यह 'देश में कुछ भी नहीं हो सकता है' के अंधकार पर 'देश यदि ठान ले, तो सब कुछ संभव है' के विश्वास की यात्रा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के देश के प्रति विजन को 135 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह से आत्मसात करते हुए जमीन पर उतारा है, उसने यह सिद्ध किया है कि सही नेतृत्व हो और नेतृत्व के पास नीति एवं नीयत हो, तो हर चुनौती से पार पाते हुए सफलता की बड़ी लकीर खींची जा सकती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल ही नहीं रहा है, अपितु विकास की नई परिभाषा भी गढ़ रहा है। आजादी के अमृतकाल में देश ने अपने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जिस तरह से चुनौती की चट्टानों पर विकास-पथ का निर्माण किया है, वह बेमिसाल है। पिछले आठ वर्षों में देश की गरीबी 22 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत से नीचे आ गई है। अत्यंत गरीबी की दर एक प्रतिशत से भी कम 0.8 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 8 वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग दोगुना हुआ है। आजादी के 70 साल में देश में केवल 6.37 लाख प्राइमरी स्कूल बने, जबकि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के केवल आठ वर्षों में लगभग 6.53 लाख प्राइमरी स्कूल बने। आठ साल में देश की साक्षरता 6 प्रतिशत से अधिक बढ़ी, जो विशिष्ट उपलब्धि है। विगत आठ वर्षों में देश में 15 नए एम्स का निर्माण हुआ। डॉक्टरों की संख्या भी पिछले आठ साल में 12 लाख से ज्यादा बढ़ी है। आठ साल में भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। सौर और पवन ऊर्जा क्षमता बीते पांच सालों में दोगुनी हुई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के देश के प्रति विजन को 135 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह से आत्मसात करते हुए जमीन पर उतारा है, उसने यह सिद्ध किया है कि सही नेतृत्व हो और नेतृत्व के पास नीति एवं नीयत हो, तो हर चुनौती से पार पाते हुए सफलता की बड़ी लकीर खींची जा सकती है

देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। 2012-13 में देश में खाद्यान्न का उत्पादन 255 मिलियन टन था, जो 2021 में बढ़कर 316.06 मिलियन टन हो गया है। यह आजादी के बाद अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। कोविड जनित मंदी के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात हुआ। नरेन्द्र मोदी सरकार के आठ वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जितने काम हुए, उतने आजादी के 70 सालों में भी न हुए। पिछले दो वर्षों से मोदी सरकार 3.40 लाख करोड़ रुपये की लागत से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों तक जरूरी राशन मुफ्त पहुंचा रही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण योजना है। इस कदम की पूरे विश्व ने सराहना की है। आयुष्मान भारत के रूप में देश में पहली बार आमजन को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला। पहली बार किसानों और मजदूरों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था हुई। पहली बार किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना शुरू हुआ। ऑर्गेनिक खेती को लेकर भी पहली व्यवस्थित नीति हमारी सरकार ने ही बनाई।

सरकार की योजनाओं ने न केवल देशवासियों को सशक्त बनाया, बल्कि देश के अर्थचक्र को भी मजबूत किया। यही कारण है कि बदले हुए वैश्विक परिवेश के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनी हुई है और भारत की विकास दर दुनिया में लगातार अधिक बनी हुई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल, गति शक्ति योजना, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव और मोनेटाइजेशन जैसी योजनाओं ने देश को विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है।

पहले समस्याओं को ही नियति मान लिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी समस्याओं का स्थाई समाधान कर देश को इनोवेटिव अप्रोच के लिए तैयार किया। प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर अनुच्छेद 370 धराशायी हुआ, अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक 1,800 अप्रासंगिक पुराने कानूनों में से 1,450 को खत्म किया जा चुका है। देश की विदेश नीति ने एक नया इतिहास रचा है। आज पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति की सराहना होती है। पहली बार देशहित में विदेश नीति का रूपांतरण हुआ है। इराक, यमन, अफगानिस्तान से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध तक, भारत के बचाव और राहत अभियान की तो पूरी दुनिया कायल है। चाहे आतंकवाद का विषय हो, वैकल्पिक ऊर्जा का विषय हो, अंतरराष्ट्रीय सौर-ऊर्जा संगठन की बात हो, कार्बन उत्सर्जन का विषय हो, रूस-यूक्रेन युद्ध की बात हो, क्वाड हो या अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध हों, हर अवसर पर भारत की विदेश नीति शानदार रही है। प्रधानमंत्री ने देश की महान सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए प्रगति को नया आयाम दिया है।

पिछले आठ वर्ष में भाजपा ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सफलता के नए कीर्तिमान रचे हैं। 18 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी बनी है। 2014 में सात राज्यों में भाजपा और हमारे सहयोगियों की सरकारें थीं। आज 18 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। पहली बार राज्यसभा में भाजपा 100 के आंकड़े तक पहुंची है। गुजरात से लेकर जम्मू-कश्मीर तक और राजस्थान से लेकर हैदराबाद तक, स्थानीय निकाय चुनावों में भी भाजपा ने इतिहास रचा है।

आजादी के अमृतकाल में पहली बार देशवासियों को यह एहसास हुआ है कि केंद्र में उनकी सरकार है, जो उनके लिए काम करती है। पिछले आठ वर्षों में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की अवधारणा साकार हुई है। हम एक नए भारत के पुनर्निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं, जहां सबके लिए समान अवसर हों और सब खुशहाल हों। आइए, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब मिलकर संकल्प लें कि भारतवर्ष को विश्वगुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खूब परिश्रम करेंगे और देश को समृद्ध बनाएंगे।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

अमित शाह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने केंद्र में अपने आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि को मैं नए भारत के निर्माण की यात्रा के रूप में देखता हूं। नए भारत का अर्थ एक सशक्त, सक्षम, समर्थ और आत्मनिर्भरता की भावना युक्त भारत है। यह सुखद है कि पिछले आठ वर्षों में इस भारत की आधारशिला रखने का काम मोदी जी ने किया है। इस दौरान देश के समक्ष कोविड संकट सहित अनेक बाधाएं और चुनौतियां आईं, लेकिन मोदीजी के कुशल नेतृत्व में देश ने मजबूती से उनका सामना किया और नए भारत के निर्माण की यात्रा सतत जारी रही। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया और अभी भी तमाम देश उससे उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के चलते यह महामारी हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावित नहीं कर पाई। जब दुनिया के बड़े-बड़े देश कोविड के समक्ष घुटने टेक चुके थे, तब मोदीजी ने 'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान करते हुए स्पष्ट किया कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो आपदा को भी अवसर में बदला जा सकता है।

नये भारत के निर्माण का यात्रा

आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा से जहां हताश हो रहे भारतीय जनमानस में आशा का संचार हुआ, वहीं इसके तहत घोषित बीस लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज ने अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का काम किया। सरकार के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि कोविड संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। भारत आज छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' में भारत 2015 में जहां 142वें स्थान पर था, वहीं अब 63वें स्थान पर है। भारत दुनिया का इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। मोदीजी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की राह पर चलता भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

भारत आज छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' में भारत 2015 में जहां 142वें स्थान पर था, वहीं अब 63वें स्थान पर है। भारत दुनिया का इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। मोदीजी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की राह पर चलता भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है

जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें देश के अर्थतंत्र में शामिल करते हुए मोदी जी ने यह प्रकट किया कि उनकी सरकार समावेशी विकास के माडल को लेकर आगे बढ़ने वाली है। मोदी शासन का मूलमंत्र 'सबका साथ-सबका विकास' ही सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी माडल को लेकर आगे बढ़ने वाला है। इसका उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुद्रा, पीएम किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत, सौभाग्य, आवास, डीबीटी इत्यादि योजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार ने गरीबों का न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण किया, बल्कि उन्हें सम्मान से जीने का अवसर देने का सफल भी प्रयास किया है। योजनाएं पिछली सरकारों में भी बनती थीं, लेकिन उनके क्रियान्वयन की गति मोदी सरकार की विशेषता रही है। अब योजनाओं को किसी सीमा में बांधे बिना सभी के लिए बनाया जाता है। पिछले आठ वर्षों में स्वतंत्रता के बाद पहली बार गरीब और पिछड़े सरकार में हितधारक (स्टेकहोल्डर) बने और अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जुड़े।

मोदीजी के शासन में राष्ट्रीय सुरक्षा को भी अभूतपूर्व मजबूती मिली है। आतंकवाद के प्रति यह सरकार जीरो टालरेंस का रवैया अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। अब आतंकी हमलों पर कांग्रेस सरकारों की तरह केवल निंदा-भर्त्सना करके ही कर्तव्यों की इतिश्री नहीं की जाती, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक द्वारा आतंकियों को उनके घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। यह परिवर्तन देश के नेतृत्व की मजबूती के कारण ही संभव हुआ। कांग्रेस सरकारों के समय अक्सर ऐसा भी सुनने को मिलता था कि भारतीय सेना के पास गोला-बारूद की कमी हो गई है, लेकिन अब सैन्य बलों को सभी अत्याधुनिक संसाधनों एवं उपकरणों से लैस रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

आज देश की वायु सीमा की रक्षा राफेल जैसा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान कर रहा है तो एस-400 जैसी सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणाली देश का कवच बनकर तैनात हो चुकी है। रक्षा सामग्री के लिए विदेशी निर्भरता वाले भारत ने 2019 में 10 हजार करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया और 2025 तक इसका लक्ष्य 35 हजार करोड़ रुपये करने का है। यह सब इसीलिए संभव हुआ, क्योंकि मोदी सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति नहीं, राष्ट्रहित का विषय है। हमारी सरकार इससे कोई समझौता नहीं कर सकती।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर तो देश को सुदृढ़ किया ही है, विश्व पटल पर भारत के गौरव को बढ़ाने का भी काम किया है। जलवायु संकट पर दुनिया को राह दिखाना हो या कोविड के विरुद्ध भारत की लड़ाई को विश्व के लिए मिसाल बनाना हो, उन्होंने विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जब किसी भी देश या वैश्विक मंच पर जाते हैं, तो उनके वक्तव्यों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भरपूर उल्लेख होता है। इससे वह विश्व को भारत के प्रति एक नई दृष्टि देते हैं। अब भारत किसी महाशक्ति के सामने झुके बिना देशहित में अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक रखता है। मोदीजी को संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व के कई मंच और देश सम्मानित कर चुके हैं। यह भी विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का ही द्योतक है। पिछले आठ वर्षों में भारत की महान संस्कृति और परंपराओं को पुनर्स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारतीय संस्कृति को वैश्विक सम्मान भी मिला है। योग को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलना इसका एक उदाहरण है।

यदि मोदीजी देशहित में बड़े और कड़े निर्णय लेते हैं तो इसका एक प्रमुख कारण उनके प्रति जनता का अपार विश्वास है। आज उनके नेतृत्व पर जनता का ऐसा विश्वास है कि लोग उनके निर्णयों को स्वयं आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान हो, गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील हो, नोटबंदी का निर्णय हो या कोविड के दौरान लाकडाउन की घोषणा, इन सभी मामलों में मोदी जी के आह्वान

आज देश की वायु सीमा की रक्षा राफेल जैसा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान कर रहा है तो एस-400 जैसी सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणाली देश का कवच बनकर तैनात हो चुकी है। रक्षा सामग्री के लिए विदेशी निर्भरता वाले भारत ने 2019 में 10 हजार करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया और 2025 तक इसका लक्ष्य 35 हजार करोड़ रुपये करने का है।

पर जनता ने जिस तरह से सरकार का सहयोग किया वह उनके प्रति लोगों के विराट विश्वास को ही दर्शाता है। मोदी सरकार एक ऐसे समय अपने कार्यकाल के आठ वर्ष पूरी कर रही है, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये आठ वर्ष अगले 25 वर्षों के लिए देश को आगे ले जाने की दशा-दिशा तैयार करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन आठ वर्षों में नए भारत की जो मजबूत आधारशिला तैयार की है, उस पर विश्व का नेतृत्व करने वाला एक सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत आकार लेगा।

(लेखक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं) ●●●

मोदी जी की सरकार के स्वर्णिम 8 वर्ष

सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण मूलमंत्र

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा नीत सरकार ने शानदार, ऐतिहासिक 8 वर्ष पूरे किये हैं। इस आठ वर्ष की स्वर्णिम यात्रा को कम शब्दों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष इन्हें कहा जा सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में युगपरिवर्तन कारी यह यात्रा अहर्निश जारी है।

सेवा

कोरोना के इस वैश्विक संकट में देश के सभी नागरिकों के लिए विश्वप्रसिद्ध दोनों टीके के दोनों डोज मुफ्त देने की सेवा से लेकर समूचे देश के पीड़ितों तक चिकित्सा एवं अन्य तमाम राहत समग्री की सेवा। जिस प्रधानमंत्री ने अपना पदनाम ही प्रधान सेवक रख लिया हो, उसके संवेदनशील नेतृत्व में केंद्रीय सत्ता और संगठन को सेवा का पर्याय ही बना दिया गया।

सुशासन

समूचा देश आज लगभग दंगामुक्त हो गया है। साम्प्रदायिक और तुष्टिकरण की राजनीति को विराम लगा है। कश्मीर से कन्यामुमारी तक भारत की एकता और अखंडता जितनी आज मजबूत है, वैसा पहले कभी नहीं रही। दुनिया भर में आज मोदी जी के सुशासन की पहचान है। अनेक वैश्विक संगठनों ने मोदी जी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता का ख़िताब दिया है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है।

गरीब कल्याण

देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों तक अनवरत खाद्यान की आपूर्ति कोरोना के वैश्विक संकट के दौरान सुनिश्चित करते रहने से बड़ा गरीब कल्याण और क्या हो सकता है भला? मोदी जी ने सभी गरीबों के सर के छत की चिंता की, शुद्ध नल जल उपलब्ध कराने से लेकर उन्हें आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त चिकित्सा से लेकर तमाम कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ा। पिछले 8 वर्षों में देश की गरीबी 22% से घट कर 10% से नीचे आ गई है। कोरोना संकट के बावजूद अत्यंत गरीबी की दर भी 1% से कम 0.8% पर स्थिर बनी हुई है। पहले देश में एक सामान्य सोच थी कि इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। अब आम जनमानस में यह धारणा बनी है कि मोदी है तो मुमकिन है। 8 साल की यह यात्रा देश की सोच को बदलने की यात्रा है। पहले सरकार जनता से कहती थी- "हुआ तो हुआ"। अब जनता कह रही है - जो कभी नहीं हुआ, वह मोदी जी के शासन काल में हुआ। ये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा है, विश्वगुरु के पद पर भारत के प्रतिष्ठित करने का मार्ग बनाने की यात्रा है। 8 वर्ष की यह यात्रा आत्मनिर्भर भारत की "संकल्प से सिद्धि" के रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत देश का रास्ता भी है और संकल्प भी। आत्मनिर्भरता में देश के अनेक मुश्किलों का हल है।

बदलाव की कहानी, प्रगति की निशानी

पहले योजनायें कागज़ पर ही बनती थी, कागज़ पर ही लागू होती थी और कागज़ पर ही पूरी हो जाती थी। आज जनता यह देख रही है कि जिस योजना का शिलान्यास होता है, वह योजना उसी कार्यकाल में पूरी भी होती है। बीते 8 वर्ष कागज़ से क्रियान्वयन और अमलीकरण की यात्रा के रहे हैं। मोदी जी की हर योजना अंतिम लाभार्थी तक पहुँचने के परिणाम यह रहे हैं कि :-

- 8 वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। 2014 में 79 हजार रुपये सालाना, अब डेढ़ लाख रुपये हो गया है।
- विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग दोगुना हुआ है। 2014 में 300 अरब डॉलर, अब लगभग 600 अरब डॉलर
- आजादी के 70 साल में देश में केवल 6.37 लाख प्राइमरी स्कूल बने जबकि मोदी जी की सरकार के केवल 8 वर्षों में 6.53 लाख प्राइमरी स्कूल बने।
- विगत 8 वर्षों में देश में 15 नए एम्स का निर्माण हुआ जबकि आजादी से 2014 तक देश में केवल 7 एम्स थे, उसमें से भी 6 श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बने।
- डॉक्टरों की संख्या भी पिछले 8 साल में 12 लाख से ज्यादा बढ़ी है। 8 साल में लगभग 170 नए मेडिकल कॉलेज बने।
- 8 साल में भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुँच गया। पिछले 8 साल में मोदी जी की सरकार ने लगभग तीन लाख 25 हजार किमी सड़क निर्माण को मंजूरी दी है।
- सौर और पवन ऊर्जा में भारत की क्षमता बीते पांच सालों में दोगुनी हुई।
- 2012-13 में देश में खाद्यान्न का उत्पादन 255 मिलियन टन था जो 2021-22 में बढ़ कर 316.06 मिलियन टन हो गया है। यह आजादी के बाद अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है।
- कोविड के कारण उत्पन्न मंदी के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दस महीने में भारत के कृषि निर्यात में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- 2009 से 2014 (मनमोहन सरकार) के पांच सालों में कृषि बजट में 8.5% की वृद्धि हुई थी, वहीं 2014 से 2019 के बीच कृषि बजट में 38.8% की वृद्धि हुई।
- 2009-10 में मनमोहन सरकार में जो कृषि बजट था, अब वह 10 गुना बढ़ गया है।
- 2013-14 में भारत की जीडीपी 112.33 लाख करोड़ रुपये के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी दोगुने से भी अधिक यानी 232.14 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।
- खादी के विकास के लिए आजादी के 70 सालों तक कोई काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद पहली बार खादी उत्पादों ने एक साल में 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

डीबीटी योजना

जैसा कि राजीव गांधी जी ने कहा था, दिल्ली से निकला एक रुपया ज़मीन पर मात्र 10 पैसा बन कर पहुंचता है, अब डीबीटी के तहत शत-प्रतिशत पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाना संभव हुआ है। जीरो लीकेज। 8 वर्षों में लाभार्थियों को अब तक श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने 225 ख़रब रुपये ट्रांसफर किये हैं जो गरीबों के सशक्तिकरण का एक प्रमुख टूल बन कर उभरा है। JAM (जन-धन, आधार और मोबाईल) ने लाभार्थियों तक शत-प्रतिशत सरकारी सहायता का पहुंचना सुनिश्चित किया है। पहली बार किसी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी को आम जनता से जोड़ा। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत और सौभाग्य योजना के कारण देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई और मंदी के बावजूद देश की विकास दर दुनिया में सर्वाधिक बनी रही।

गरीब कल्याण अन्न योजना

पिछले दो वर्षों से मोदी सरकार 3.40 लाख करोड़ रुपये की लागत से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों तक जरूरी राशन मुफ्त पहुंचा रही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण योजना है।

किसान सम्मान निधि

देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी दे रहे हैं। अब तक 10 किस्तों में किसानों को 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। अगली क़िस्त कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी जारी करने वाले हैं। इसके अलावा एमएसपी पर धान खरीदी से लेकर उर्वरकों पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।एक बोरा यूरिया पर 3 हज़ार से अधिक तो डीएपी पर 2 हज़ार से अधिक अनुदान मोदी जी दे रहे हैं।

आयुष्मान भारत

देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। अब तक तीन करोड़ से अधिक लोग लाभ ले चुके हैं। 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी ।

जल जीवन मिशन

9 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाने की शुरुआत हो गई है। इस वर्ष लगभग चार करोड़ घरों को इससे जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सौभाग्य योजना

हर गाँव बिजली पहुँचाने के बाद मोदी सरकार ने हर घर तक बिजली पहुंचाने का बीड़ा हाथ में लिया है। अब तक 2 करोड़ 81 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। 36 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किये जा चुके हैं।

उज्ज्वला योजना

9 करोड़ महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। उनका स्वास्थ्य भी सुधरा है और जीवन स्तर भी।

प्रधानमंत्री आवास योजना

अब तक इसके तहत 2.38 करोड़ से अधिक घर गरीबों के लिए बनाये जा चुके हैं।

स्वच्छ भारत अभियान

ये पूरे भारत का आंदोलन बना। देश में लगभग 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। आज पूरा भारत खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त की ओर है। इससे गरीब लोगों को बीमारियों से लड़ने में भी काफी सहायता मिली है।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 34 करोड़ से अधिक लोन वितरित किये जा चुके हैं।
- जन-धन योजना में 45 करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच स्तम्भ अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, डेमोग्राफी, मांग और सिस्टम

- हर गाँव में इंटरनेट कनेक्शन और कॉमन सर्विस सेंटर, हर गाँव में ऑप्टिकल फाइबर का

जाल

■ हर गाँव को राजमार्ग से जोड़ने की पहल, हर गाँव तक पक्की सड़कें

खाद्य सुरक्षा

खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

200 से ज्यादा रक्षा उपकरणों की विदेश से खरीद पर रोक

अन्तरिक्ष क्षेत्र में महाशक्ति बना भारत, एक साथ 100 से अधिक सैटेलाईट लांच कर मिशन चंद्रयान और मिशन मंगलयान पर फोकस। सेल्फ हेल्प गुप्स, वर्किंग प्लेस पर सुरक्षा, सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन, मुद्रा लोन में - प्राथमिकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम समर्थ योजना मातृत्व आश्वासन सुमन योजना इत्यादि योजनाओं से हो रही है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पहल सुरक्षित की।

■ किसान सम्मान निधि के साथ कृषि सेक्टर के के लिए 1 लाख करोड़ रुपये (FPOs के लिए)

■ डिजिटल इंडिया से आई देश में क्रांति

■ वन नेशन वन राशन कार्ड से मजदूरों की सहायता

सभी विवादित समस्याओं का समाधान, विकास की ओर नई उड़ान

2014 से पहले समस्याओं को ही नियति मान लिया गया था। देश की जनता ने तो यह सोचना ही छोड़ दिया था कि ये समस्याएं कभी ख़त्म भी हो सकती हैं। लेकिन धरती पुत्र श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा ही कुछ और थी। उन्होंने सभी समस्याओं का स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान कर राष्ट्र को विकास की धारा के साथ जोड़ दिया।

■ जम्मू-कश्मीर बना भारत का अभिन्न अंग और धारा 370 हुआ निष्प्रभावी।

■ अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर बनने का सपना हुआ पूरा।

■ ट्रिपल तलाक से मिली मुस्लिम महिलाओं को आजादी।

■ नागरिकता संशोधन कानून संसद में हुआ पारित ।

■ आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान।

■ गरीब सवर्णों को आरक्षण |

■ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता

■ वन रैंक, वन पेंशन

■ वन नेशन, वन राशन कार्ड

■ 1450 पुराने और बेकार कानूनों से मिली जनता को राहत

■ ऐतिहासिक श्रम सुधार क़ानून क्रियान्वित । ई-श्रम कार्ड से करोड़ों मजदूरों को लाभ

संस्कृति को दिया सम्मान

■ नागरिकों में जगाया देश के लिए अभिमान

■ अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण

■ दिव्य कशी, भव्य काशी का सपना हुआ साकार ।

■ बाबा केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार

■ सोमनाथ का विकास

■ स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी का निर्माण लौह पुरुष को सम्मान

■ बाबा साहब भीमराव से जुड़े पंचतीर्थ का निर्माण

■ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित जनजातीय संग्रहालय का निर्माण

■ संविधान दिवस, सामाजिक समरसता दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, जनजातीय गौरव दिवस और योग दिवस की शुरुआत

■ नेशनल वॉर मेमोरियल और प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण

■ रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की कूटनीति की सराहना तो हमारे दुश्मन भी कर रहे हैं। भारत ने अपने 23 हजार छात्रों की सकुशल वतन वापसी कराई।

कोविड प्रबंधन

■ स्वयं के साथ ही विश्व - कल्याण की भावना से मोदी सरकार ने किया काम

■ वसुधैव कुटुंबकम दुनिया के 100 से अधिक देशों को दवाई से मदद,

■ केवल 9 महीने में भारत ने दो-दो कोविड वैक्सीन विकसित किये

■ अब तक देश में 192 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हुए। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक दिन में ढाई करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड।

■ मेडिकल ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर अभियान | अब देश में कहीं भी ऑक्सीजन और दवाइयों की दिक्कत नहीं।

2014 से पहले देश की जनता

■ परेशान थी नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार से

■ परेशान थी नीतियों में शिथिलता की तत्कालीन सरकार की आदत से।

■ परेशान थी जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति से।

आजादी के 70 साल बाद भी

■ देश के सभी गांवों तक बिजली नहीं, गरीबों के बैंक खाते नहीं । गरीबों के घर में गैस चूल्हे नहीं ।

■ नागरिकों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा नहीं।

■ गरीबों के लिए कोई आयुष्मान भारत जैसा सरकारी मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध नहीं ।

■ गरीबों को उनके हक की रकम मिलने की गारंटी नहीं।

कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ अग्रसर। आठ साल में हुए 50 विधानसभा चुनाव में से 41 में कांग्रेस को दी मात। मोदी जी ने अपने विजन और जन कल्याणकारी योजनाओं से दिया जीत का मंत्र। सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास के मंत्र से कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति पूरी तरह भरभराकर बिखर गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब मिलाकर 680 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस बमुश्किल 56 पर जीत सकी। उत्तर प्रदेश में उसके 387 उम्मीदवारों के जमानत जब्त हुए। आज केवल दो राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। झारखंड और महाराष्ट्र में वो छोटे सहयोगी दल की भूमिका में है।

हाल के पांच राज्यों में चुनाव पांचों में हारी कांग्रेस, चार में बीजेपी की डबल इंजन सरकारें।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव हुए। 1985 के बाद पहली बार था जब कांग्रेस यूपी की सभी सीटों पर उतरी, लेकिन मात्र 2 सीटें ही जीत सकी। पंजाब से भी कांग्रेस की विदाई हो गई। ●●●

शुचिता का सवाल और कांग्रेस

नेशनल हेराल्ड मामले का जिन्न एकबार फिर बोतल से बाहर निकला है। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होने का नोटिस हुआ तो मानो कांग्रेस में भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा देश के अलग-अलग शहरों में प्रेस कांफ्रेंस से लेकर विरोध प्रदर्शन तक आयोजित किये गये। हालांकि सोनिया गांधी अस्वस्थता के चलते पेश नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ईडी के सामने दो चरणों में पूछताछ के लिए पेश हुए। मगर इससे इतर सवाल है कि क्या नेहरु-इंदिरा परिवार व्यवस्था से ऊपर हैं? किसी भी मामले क्या जांच प्रक्रिया के जो नियम कानूनी तौर पर लागू हैं, वो कांग्रेस पार्टी के 'परिवार-विशेष' पर नहीं लागू होते?

शिवानंद द्विवेदी

इस पूरे मामले पर नजर डालें तो सितंबर 1938 में शुरू हुए नेशनल हेराल्ड के दिल्ली संस्करण का प्रकाशन मार्च 2008 तक चला। इससे पहले 1995 में कर्मचारियों के वेतन आदि का हवाला देकर इसके लखनऊ संस्करण को नीलाम किया जा चुका था। जब नेशनल हेराल्ड का लखनऊ संस्करण नीलाम हुआ तो अटल विहारी वाजपेयी ने कहा था, 'जो हेराल्ड नहीं चला सकते, वो देश क्या चलाएंगे।' 2008 में तकनीकी अक्षमता का हवाला देकर इसका दिल्ली संस्करण भी बंद कर दिया गया। इसी के बाद नेशनल हेराल्ड मामले में पैसों का ऐसा घुमावदार मकड़जाल फैला, जिसके घेरे में सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं उनके बेटे राहुल गांधी आ चुके हैं।

गौर करने वाला तथ्य है कि 2008 में अखबार बंद होने के बाद कांग्रेस नें नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का ब्याजमुक्त कर्ज दिया था। किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी निजी कंपनी को कर्ज देना अपने आप में आरपीए नियमों का उलंघन है। हालांकि मामला यही खतम नहीं होता बल्कि इसके तार आगे भी और संदिग्ध रूप में जुड़ते जाते हैं। कांग्रेस द्वारा दिये गए ब्याजमुक्त कर्ज के बाद अखबार

शुरू नहीं होता बल्कि चार साल बाद 26 अप्रैल 2012 को अखबार के प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का मालिकाना हक यंग इण्डिया कंपनी को मात्र 50 लाख में दे दी जाती है। जिस यंग इंडिया को एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड अर्थात नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक दिया गया, उस कम्पनी में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की संयुक्त तौर पर 76 फीसद की साझेदारी थी। बाकी शेष 24 फीसद में आस्कर फर्नांडिस एवं मोतीलाल वोहरा साझेदार थे।

एक और बात है जो इस पुरे मामले के झोल को घोटाले की स्थिति तक पहुंचाती हैं वो है कि जब मात्र 50 लाख में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की अधिकतम साझेदारी वाली यंग इण्डिया एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड अर्थात नेशनल हेराल्ड का अधिग्रहण कर रही थी, उस दौरान नेशनल हेराल्ड की परिसम्पतियाँ लगभग 1600 करोड़ के आसपास थी।

एक तरह से देखा जाए तो लगभग 1600 करोड़ की परिसंपतियां महज 50 लाख में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी को हासिल हो गयीं। यह सौदा अपने आप में आश्चर्यजनक है। परिणामतः लेन-देन और हेर-फेर के इस पुरे मसले में दो स्तर पर सवाल उठ रहे हैं।

पहला सवाल तो खुद कांग्रेस पार्टी के ऊपर उठ रहा है। आरपीए एक्ट एवं आयकर विभाग के मुताबिक़ यह स्पष्ट नियामक तय है कि कोई भी राजनैतिक दल किसी व्यापारिक कारोबार आदि में बिलकुल भी निवेश नहीं कर सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर इस प्रकार का कोई आरोप अगर किसी राजनीतिक दल के ऊपर साबित होता है तो उसकी चंदे में मिली आयकर छूट को रद्द कर दिया जाएगा। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए।

दूसरा जो आरोप बनता दिख रहा है वो सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सवालों के कटगरे में खड़ा करता है। स्वाभाविक तौर पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की कंपनी को लाभ पहुंचाया गया है। सवाल है कि आखिर अनैतिक रूप से ही मगर नब्बे करोंड़ के कर्ज के बावजूद नेशनल हेराल्ड शुरू होने की बजाय बंद क्यों हो गया ? 1600 करोंड़ की सम्पतियों वाले समूह को नब्बे करोंड़ कर्ज लेने के बाद मात्र पचास लाख में बिकने की नौबत क्यों आ गयी? जिस कंपनी नें 1600 करोंड की सम्पतियों वाले एसोसिएट जर्नल्स को मात्र पचास लाख में अधिग्रहित किया उस समूह का अधिकतम हिस्सेदार सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी का होना महज इत्तेफाक तो नहीं ही कहा जा सकता है? इन तमाम सवालों के तार आपस में उलझते हुए सिर्फ एक जगह जाकर जुड़ते हैं और वो जुड़ाव नेहरू-गांधी परिवार से सीधा नजर आता है।

एक और बात है जो इस पुरे मामले के झोल को घोटाले की स्थिति तक पहुंचाती हैं वो है कि जब मात्र 50 लाख में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की अधिकतम साझेदारी वाली यंग इण्डिया एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड अर्थात नेशनल हेराल्ड का अधिग्रहण कर रही थी, उस दौरान नेशनल हेराल्ड की परिसम्पतियाँ लगभग 1600 करोंड़ के आसपास थी।

इस मामले में एक और नेता मोतीलाल वोरा, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, की भूमिका भी कम रोचक नहीं है। मोतीलाल वोरा का जुड़ाव कांग्रेस के कोष विभाग से गहरा रहा। सौदे के दौरान वे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड में भी महत्वपूर्ण भूमिका में भी रहे। वोरा यंग इण्डिया में भी एक साझीदार रहे। अर्थात, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए कागजों पर कोई खेल रच रहा था तो उसमें एक मोतीलाल वोरा भी थे।

ऐसे में यहाँ पूरा मामला अवैध ढंग से एक सम्पति को दूसरे के नाम से हस्तांतरित करने का भी नजर आता है। फिलहाल इस मामले में कई सवाल हैं जिनकी सत्यता को न्याय की कसौटी पर कसा जाना है।

कांग्रेस शोर-शराबे से इस मामले को राजनीतिक रंग भले दे रही हो, लेकिन यह सच है कि मामला एक 'परिवार-विशेष' के निजी हितों के लिए किये अनैतिक तथा अनियमिततापूर्ण आचरण की दुर्लभ मिसाल हैं। महज एक परिवार के हितों में एक राजनीतिक दल का संलिप्त हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण एक निजी भ्रष्टाचार के मामले को पार्टी का एजेंडा बनाकर उसे राजनीतिक रंग देना है। कांग्रेस को इससे बचना चाहिए था। मगर कांग्रेस की दुविधा यह है कि वह 'परिवार विशेष' के साए से न तो निकल पाती है और न ही निकलने का कोई रास्ता दिखाई देता है।

एक राजनीतिक दल की भारत के लोकतंत्र में जो भूमिका होनी चाहिए, कांग्रेस उस भूमिका को लेकर मानों जरा भी गंभीर नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आर्थिक अनियमितता को लेकर कोई मामला है तो इसे कांग्रेस द्वारा पार्टी का मामला बना लेना, कांग्रेस की निर्बलता को ही प्रदर्शित करता है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र में उनकी भूमिका क्या महज एक परिवार के लिए 'सेफ-गार्ड' बनकर कठपुतली की तरह नाचने की रह गयी है ?

लेखक गृहमंत्री अमित शाह की राजनीतिक जीवनी के लेखक हैं। ●●●

भारत ने महामारी से निपटने के लिए एक जन केंद्रित रणनीति अपनाईः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्री मोदी ने 'महामारी की थकान की रोकथाम और तैयारी को प्राथमिकता' विषय पर शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने महामारी से निपटने के लिए एक जन केंद्रित रणनीति अपनाई और इस साल अपने स्वास्थ्य बजट के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया है। श्री मोदी ने कहाकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है और अपनी करीब नब्बे प्रतिशत वयस्क आबादी और पचास मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण कर चुका है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में भारत अपनी सस्ती स्वदेशी कोविड शमन प्रौद्योगिकियों, टीकों और चिकित्सा विज्ञान को दूसरे देशों के साथ साझा करके सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा।

दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन

श्री मोदी ने 'महामारी की थकान की रोकथाम और तैयारी को प्राथमिकता' विषय पर शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

सत्य कभी पराजित नहीं होता, सोनिया गांधी और राहुल गांधी माफी मांगें : विष्णुदेव साय

प्रछत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाने पर कहा है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। जान बूझकर लगाए गए आरोप देश की सबसे बड़ी अदालत में टिक नहीं पाए। गुजरात दंगों में मोदी का नाम घसीटकर राजनीति करने वालों का झूठ बेनकाब हो गया है। कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके उन सभी चाटुकारों को माफी मांगनी चाहिए जो इतने सालों से मोदी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस नेता मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें मौत का सौदागर कहते नहीं थक रहे थे। मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने एसआईटी का बेधड़क सामना किया। मोदी को एसआईटी से क्लीन चिट मिली तो विरोधियों को रास नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वहां सच की जीत होनी ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय कर दिया है। अब ओछी राजनीति करने वाले कांग्रेस नेताओं में रत्ती भर भी नैतिकता बाकी बची हो तो वे बिना शर्त माफी मांगें।

जनता का जीवन आसान बनाना मोदी जी की प्राथमिकता : भानु प्रताप

भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य उद्योग मंत्री भानुप्रताप सिंह वर्मा ने आज जिला भाजपा की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जिलेभर से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 70 वर्षों में पिछली सरकारों ने जनता की मूलभूत सुविधाओं की चिंता नहीं की थी, परंतु मोदी सरकार ने जनता की जीवन शैली की सुगमता की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि जीवन शैली की सुगमता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है इसलिए इसे आगे बढ़ाना केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक घर में शौचालय, हर घर में नल हो इस हेतु जल जीवन मिशन,प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना,घर घर बिजली इत्यादि योजनाओं के माध्यम से देशभर के गरीबों के जीवन में एक विश्वास का भाव मोदी सरकार ने पैदा किया है। जिसके कारण जनसंघ से लेकर आज तक भाजपा जीतनी घोषणा पत्र में बातें किया करती थी, वह सभी बातें धीरे-धीरे पूरी हो रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, ट्रिपल तलाक एवं अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर अब कोर्ट के आदेश के बाद मूर्त रूप ले रहा है। पुरानी योजनाओं का पूरा होने का क्षण, यह भाजपा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है । श्री वर्मा ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता देवतुल्य हैं । नाराजगी जताते तो हैं, परंतु समय आता है तो सरकार बनाने हेतु जी जान से जुट जाते हैं, ऐसे देव तुल्य कार्यकर्ताओं का वह अभिनंदन करते हैं । श्री वर्मा ने कार्यकर्ताओं को आगामी मिशन में जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहते हैं ।

किसान विरोधी कृषि मंत्री को बर्खास्त किया जाये : भाजपा

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रभारी संदीप शर्मा ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे पर हमला बोलते हुए कहा है कि कृषि मंत्री द्वारा लगातार खाद की आपूर्ति को लेकर गलत बयानी की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप खाद की कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है, किसानों का शोषण होता है। इसी प्रकार की बयानबाजी पिछले साल भी की गई थी और कहा गया था कि खरीफ के लिए केंद्र ने मात्र 6 लाख टन खाद ही दिया गया। जबकि बाद में राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में 11.8 लाख टन खाद का वितरण बताया गया। कृषि मंत्री ऐसा बयान देकर किसानों में आपाधापी फैलाकर फर्जी जैविक खाद किसानों को टिका कर गोबर घोटाला की वसूली किसानों से कराना चाहते हैं और षड्यंत्र पूर्वक केंद्र सरकार को बदनाम करना चाहते हैं।

खाद के अग्रिम उठाव का कार्य अप्रैल माह में ही शुरू हो जाना चाहिए परंतु समय पर यह सरकार कुंभकर्णी नींद में सोए रहती है। अग्रिम उठाव कार्य में एक से डेढ़ माह विलंब होने से भी वितरण में असुविधा होती है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना होता है और कलाबाजारियों को मौका मिलता है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने कहा कि रविन्द्र चौबे छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता हैं। सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, निर्णयों और प्रदेश से जुड़े तथ्यों को सामने लाने की जिम्मेदारी है। वे सरकार के प्रवक्ता हैं तो उनकी बात सरकार का कथन होती है लेकिन रविन्द्र चौबे इस सरकार के ऐसे प्रवक्ता हैं जो कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं और सरकार अपने प्रवक्ता की गलतबयानी के बाद अलग तथ्य जाहिर कर यह साबित कर देती है कि सरकार के प्रवक्ता मंत्री जनता में भ्रम फैलाकर खाद की जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा नेता संदीप शर्मा ने कहा कि यह समझ से परे है कि भूपेश बघेल सरकार के कृषि मंत्री किसानों के दुश्मन क्यों बन बैठे हैं।

खाद पर गलतबयानी करके मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं चौबे

मोदी सरकार कर रही किसान हितकारी निर्णय : विष्णुदेव

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान के समर्थन मूल्य में सौ रुपये की वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सहित देश के किसानों को सामान्य धान का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य सौ रुपये बढ़ाकर मोदी जी ने 2040 कर दिया है। इस फैसले का सर्वाधिक फायदा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का अभिनंदन है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार देश के किसानों की समृद्धि के लिए अभूतपूर्व कदम उठा रही है। देश के किसानों को सम्मान मिल रहा है। निधि मिल रही है। जबकि तथाकथित न्याय का नगाड़ा बजाने वाली कांग्रेस और उसकी राज्य सरकार किसानों को तीन साल से ठग रही है। किसानों को हर साल बढ़ रहे समर्थन मूल्य को जोड़कर प्रति क्विंटल 2500 से अतिरिक्त राशि देने की मांग भाजपा लगातार करती रही है और आज धान के समर्थन मूल्य में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा की गई सौ रुपये की वृद्धि पर राज्य सरकार से यह मांग हम दोहरा रहे हैं कि भूपेश बघेल बिना किसी बहानेबाजी के किसान को वर्ष 2019 से आज तक हुई समर्थन मूल्य वृद्धि की अंतर की राशि 2500 के अतिरिक्त जोड़कर एकमुश्त भुगतान करें।

पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के नवनिर्मित मकानों का फीता काटकर उन्हें गृह प्रवेश कराया।

बिलासपुर में डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति दिवस पर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पुराना बस स्टैण्ड में स्थापित डॉ.मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पाजंलि अर्पित की।

भूपेश सरकार ने 16 लाख महिलाओं को किया बेघर : स्मृति ईरानी

भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में भूपेश बघेल को ललकारते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा भूपेश जी याद रखें अमेठी में जिस कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आप हम से टकराए थे उसकी जमानत जब्त हो गई थी और हम तो भारतीय जनता पार्टी के वो अदने से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट तक जब्त कर दी थी। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार ने 16 लाख आवास नहीं 16 लाख महिलाओं का सम्मान वापस किया है। भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महिला मोर्चा की बहनों को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा सबसे पहले आप बहनों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शक्ति को प्रणाम करती हूं। भाजपा में महिला मोर्चा एक सशक्त दंड है जो आज देश की ढाल बनकर खड़ी है। परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाले लाखों-करोड़ों कार्यकर्ताओं के पीछे शक्ति बनकर खड़ी उनके घर की महिलाओं को भी प्रणाम करती हूं जिन की हिम्मत से ही आज वे निस्वार्थ भाव से भाजपा के लिए कार्य कर रहे और राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से कहा कि याद रखें राजनीति एक कठिन डगर है परंतु सिद्धि हमेशा संकल्प से ही मिलती है। आप हमेशा याद रखें कि बड़ों का सम्मान करते हुए छोटो के सामने झुकने में ना हिचकिचाए यह आपकी संकल्प में सहायक होता है । याद रखें आज की महिलाओं को किसी सहारे की जरूरत नहीं बल्कि अब समय हो गया है कि आप सब का सहारा बने। उन्होंने कहा की ये डिजिटल युग है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दीक्षा एप के जरिए आपको रास्ता दिखाया है कि आप डिजिटल साक्षर हो। इस ऐप के माध्यम से देश में दो करोड़ 60 महिलाएं डिजिटली साक्षर हो गई है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि हिंदुस्तानी महिला को सिर्फ रास्ता दिखा दो समाधान वे स्वयं ढूंढ लेती है। महिलाओं मोर्चा की बहनों का आवाहन करते हुए उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि हमारा प्रधान सेवक बिना थके लगातार काम कर रहे हैं तो फिर हम कैसे थक सकते हैं।

हसदेव अरण्य मामले में यदि राहुल सही हैं तो, सीएम भूपेश को बर्खास्त करें: बृजमोहन अग्रवाल

पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने हसदेव अरण्य पर प्रेस वार्ता लेते हुए कहा कि भूपेश सरकार अपने नेता सोनिया गांधी और अपने बड़े भाई अशोक गहलोत को खुश करने के लिए छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के हितों की बलि दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को बताएं जो प्रोजेक्ट 3 वर्षों से रुका हुआ था आखिर किसके दबाव में मात्र 3 महीनों में उसे स्वीकृति दे दी । बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा नियम कायदे और कानून कहते हैं कि राज्य सरकार अगर पर्यावरण मंजूरी ना दें और राज्य सरकार ना चाहे तो कोई भी उनके क्षेत्र में खनन नहीं कर सकता। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेसी निजी हित में जनता को बरगलाना बंद करें । उन्होंने कहा कि शायद भूपेश बघेल जी भूल गए हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले 2018 में राहुल गांधी जी हसदेव आकर यहां की जंगल, यहां की संस्कृति और यहां की पेड़ नहीं कटने देने का वादा करके गए थे। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस अब जनता को स्पष्ट करें कि हरदेव अरण्य मामले में यदि राहुल जी सही है तो, भूपेश जी को बर्खास्त करें, भूपेश जी सही हैं तो अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें और अगर स्वास्थ्य मंत्री जी सही हंप तो जनहित मे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर सड़क की लड़ाई लड़े।

विष्णुदेव ने बघेल पर दागे सवाल-आखिर क्यों है कांग्रेस का हाल बेहाल

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पांच सवाल दागते हुए कहा है कि अब तक बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री का हाल इतना बेहाल क्यों हो गया कि वे कह रहे हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने केंद्र सरकार द्वारा फोन टेपिंग कराई जा रही है। विष्णुदेव साय ने कहा की केंद्र की भाजपा सरकार हमेशा संवैधानिक रूप से कार्य करती है परंतु छत्तीसगढ़ कांग्रेस को किस बात का भय सता रहा है?

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछे 5 सवाल

- भूपेश बघेल बताए कांग्रेस का कौन मंत्री,विधायक अनैतिक कार्य कर रहा है जिसका फोन टैप हो रहा है?
- भूपेश बघेल सरकार फोन पर ऐसे कौन से कृत्य कर रही है, जिससे फोन टेप कर ब्लैकमेल करने का भय उन्हें सत्ता रहा है?
- क्या भूपेश बघेल को अपने घर के भीतर (केबिनेट) से खतरा है? यदि है तो वे ऐसे साथियों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, जिनकी बातें उजागर होने पर भूपेश बघेल को अपनी सरकार अस्थिर होने का अंदेशा है?
- भूपेश बघेल बतायें कि उनके प्रशासनिक सहयोगियों पर पहरेदारी बढ़ाने की वजह क्या है?
- भूपेश बघेल बतायें कि अपने मंत्री द्वारा एक कलेक्टर को भ्रष्ट बताने पर अफसर या मंत्री दोनो के किसी को भी नही हटाया क्यों?

बघेल भाषायी गरिमा खोते जा रहे हैं : धरमलाल कौशिक

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांकेर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे है वह भाषायी गरिमा के खोते स्तर को बताता है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया है वह मातृशक्ति का अपमान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर सुशोभित किसी व्यक्ति को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। जिस तरह से उन्होंने संघ और भाजपा के साथ महिलाओं को लेकर जो बातें कही है यह उनके अध्ययनशीलता की कमी को भी बताता है। उन्होंने कहा कि संघ और भाजपा के संबंध में वे हमेशा आपा खोकर बेतुकी व बेबुनियादी बातें कर भ्रम फैलाने का काम करते है उन्हें संघ के गौरवमयी इतिहास व कार्ययोजना का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन वे बिना किसी अध्ययन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ भी बोल देते है। कौशिक ने कहा कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री अपने यात्रा के दौरान केवल इवेंट मैनेजमेंट का सहारा ले रहे है और उन्हें जो बातें लिखकर दी जा रही है उसे वे पढ़ लेते है। प्रदेश में सत्ता पाने के लिए प्रदेश की जनता से बड़े-बड़े वादों से प्रदेश की जनता को छला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है इसके लिए उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए और अपने दिए हुए बयान वापस लेना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छत्तीसगढ़ पोषण अभियान समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन सहाय ने किया।

प्रदेश सह प्रभारी श्री नितिन नबीन का विमानतल पर आगवानी करते प्रदेश महामंत्री (सं.) श्री पवन साय एवं भाजपा पदाधिकारीगण।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं युवाओं के दुश्मन तो नहीं : संतोष पाण्डेय

सांसद संतोष पाण्डेय ने अग्निपथ अभियान को लेकर मुख्यमंत्री के दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को भटकाने व अटकाने का कार्य सदा करती है। प्रदेश के युवाओं को नशे व अंधकार में डुबने व छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने युवाओं की चिंता करने का अधिकार खो चुकी है। यहां के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के साथ नौकरी देने का वादा कर चुकी कांग्रेस की सरकार ने संविदा से नियमितीकरण की बात कहकर हमेशा छल किया है। प्रदेश की जनता को दगा देने वाली कांग्रेस सरकार ने रेडी टू ईट अभियान से जुड़े लोगों का अधिकार छीना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से युवाओं का उपहास कर रहे हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे है यह बेहद ही निंदनीय है। जिस तरह से वे स्तरहीन बातें कर रहे हैं इसमें कांग्रेस की सोच साफ झलकती है। यही कारण है कि कांग्रेस राज्यों में सिमट कर रह गई है। जनता के जनादेश का अपमान करके केवल राहुल गांधी को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस गांधी परिवार के प्रति वफादारी निभाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने देश के युवाओं को हमेशा भ्रमित करने का कार्य किया है।

सांसद पाण्डेय का आरोप मुख्यमंत्री युवाओं को भटकाने व उनका उपहास कर रहे हैं

सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि महान क्रांतिकारी सुभाषचंद बोस के सपने को साकार करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीर व अग्निपथ अभियान के माध्यम से राष्ट्र के युवाओं को एक दर्शन व राष्ट्रभक्ति के दिशा में मजबूती से प्रशस्त किया है। उन्होंने मांग की है कि यूपी हिमाचल जैसे अन्य राज्यों में अग्निपथ अभियान से जुड़े युवाओं को स्थानीय पुलिस व सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार की प्राथमिकता देने की बात कही गई है। उस की तरह की नीति छत्तीसगढ सरकार को बनानी चाहिए और युवाओं के उपहास से मुख्यमंत्री बघेल को बचना चाहिए।

कांग्रेस हमेशा ओबीसी समाज की उपेक्षा करती रही है : संगम लाल गुप्ता

पूर्व भाजपा के प्रतापगढ़ से सांसद व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस देश में ओबीसी समाज का उपेक्षा का कारण कांग्रेस ही रहा है जो इस समाज को केवल वोट बैंक का ही आधार मानता रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे है और जब राज्यसभा में किसी छत्तीसगढ़िया को भेजने की बात होती है तो अपने दिल्ली के सामने नतमस्तक होकर मौन हो जाते है और इस बात को प्रदेश की जनता भलिभांति समझ रह है कि वे छत्तीसगढ़ी परंपराओं व लोक जीवन को पॉलिटिकल पीआर से जोड़कर केवल अपनी सियासत चमकाने में लगे है। उन्होंने कहा कि इस देश को एक ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व मिला है जो सर्वसमाज, सर्व विकास और समग्र विकास की अवधारणा को पूरा करने में जुटे है। निश्चित ही उनकी नेतृत्व में ओबीसी समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य इन आठ वर्षों में हुए हैं लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले में जिस तरह से राजनीति कर रही है वह किसी से छिपा नहीं है। जिस व्यक्ति ने आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है उसे ही प्रदेश की सरकार उपकृत कर एक संस्थान का प्रमुख बना दिया है ।

चपरासी के लिए आये आवेदनों की बाढ़ में बह गए भूपेश सरकार के दावे- ठोकने

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी नलिनीश ठोकने ने राज्य में पीएससी के जरिये हो रही सौ से भी कम चपरासी पद की भर्ती के लिये आवेदनों का ढेर लग जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी सरकार और कांग्रेस के दावे इन आवेदनों की बाढ़ में बह गए हैं। सच सामने आ गया है कि राज्य में बेरोजगारी की वास्तविक दर क्या है? भूपेश बघेल दावा करते हैं कि तीन साल में पांच लाख लोगों को नौकरी दे दी। झूठी आंकड़ेबाजी का जादू दिखाकर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर देश भर में सबसे कम है। यदि वाकई में ऐसा होता तो 80 चपरासी की भर्ती के लिए 60 हजार से ज्यादा आवेदन कहां से आ गए। अभी आवेदन करने के लिए एक हफ्ते का समय बाकी है तो यह आवेदन डेढ़ से दो लाख तक भी पहुंच सकते हैं। आंख में पट्टी बांधकर भूपेश बघेल की हां में हां मिलाने वाला कांग्रेस संगठन तो भूपेश बघेल के सफेद झूठ को सही ठहराने मनरेगा तक के आंकड़े पेश करने का हुनर दिखाने में सक्षम है। हम शुरू से कह रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार गलत आंकड़े दिखाकर गुमराह कर रही है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ गई है। कांग्रेस ने घोषणावीर बनकर रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। कितना रोजगार दिया, इसकी कलई चपरासी के लिए आई अर्जियों ने खोल दी है।

भाजपा मीडिया प्रभारी नलिनीश ठोकने ने कहा कि देश की सरकार युवाओं को महत्वाकांक्षी अग्निपथ की सौगात देकर उनका भविष्य सुरक्षित कर रही है तो भूपेश बघेल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कारनामे की वकालत करते हुए युवा पीढ़ी को बरगलाने का काम करते हैं और यहां छत्तीसगढ़ को बेरोजगारगढ़ बना दिया है। भाजपा मीडिया प्रभारी नलिनीश ठोकने ने कहा कि भूपेश बघेल दावा करते हैं कि यहां चरवाहा भी 30-35 हजार रुपये महीना कमा लेते हैं तो वे चपरासी बनने के लिए जूझ रहे पढ़े लिखे युवाओं से यह कह दें कि चरवाहा बन जाओ और बड़ी रकम कमाओ। भूपेश बघेल झूठ का सौदा करके छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र को हो रहा समग्र विकासः प्रहलाद पटेल

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सफलता पूर्वक 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 31 मई को आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल शामिल हुए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश के दस करोड़ किसानों को 21 हजार करोड़ की राशि जारी किया गया। यह केन्द्र सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास ये नारा लेकर केंद्र सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। केंद्र सरकार गांव, गरीब, किसान की सरकार है साथ प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ पेयजल के लिए जल जीवन मिशन और कृषि के क्षेत्र में किसानों के सम्मान के लिए सम्मान निधि के साथ हर वर्ग के लिए कार्य किया हैं। जिसका लाभ आज आमजन मानस को मिल रहा है। कोरोना जैसे महामारी में मुफ्त अनाज और मुफ्त वैक्सीन देकर केन्द्र सरकार ने अपनी प्रतिब्धता दिखाई है ये 8 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित किया जाता है।

भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिला द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल व सांसद सुनील सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के पास खाद का पर्याप्त भंडारण है इसके बाद भी सहकारी संस्थानों में खाद नहीं पहुंच पा रहा है जिसके कारण प्रदेश में खाद को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है।

श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने दिया आदिवासी महिला शक्ति को सम्मान

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू को एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने पर भाजपा नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए देश के आदिवासी समाज को बधाई दी है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने द्रोपदी मुर्मू को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भाजपा ने आदिवासी समाज की नारी शक्ति का अद्वितीय सम्मान किया है। द्रोपदी मुर्मू भारत में आदिवासी समाज से पहली राज्यपाल बनीं और अब वे भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। शिक्षक से लेकर राज्यपाल और अब राष्ट्रपति पद का सफर उनकी योग्यता का प्रतिफल है। भाजपा अनुसूचित जाति, आदिवासी पिछड़ा वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों का सम्मान करते हुए यह चाहती है कि सभी को समान अवसर मिले इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के उत्तराधिकारी के रूप में भाजपा ने द्रोपदी मुर्मू का चयन किया है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह,संगठन महामंत्री पवन साय , नेता प्रतिपक्ष

धरमलाल कौशिक, वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम, ननकीराम कंवर, रेणुका सिंह, विक्रम उसेंडी, सांसद मोहन मंडावी, केदार कश्यप, महेश गागड़ा, लता उसेंडी, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय, सांसद सुनील सोनी, विजय बघेल, संतोष पांडेय, वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, किरण देव , नारायण चंदेल, राजेश मूणत, नगर भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सहित ,भाजपा मीडिया प्रभारी नलिनीश ठोकने सभी भाजपा नेताओं ने द्रोपदी मुर्मू को लेकर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

भूपेश बघेल ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे उन्हें डर सता रहा हैः विष्णुदेव

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिल्ली में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भूपेश बघेल ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे उन्हें डर सता रहा है और वे कह रहे हैं कि अगला नम्बर छत्तीसगढ़ का है। अगर उनका इशारा महाराष्ट्र की महामिलावट सरकार के भीतर मची भगदड़ की तरफ है तो भूपेश बघेल यह भी जानते हैं कि जो असंतोष महाराष्ट्र में है, वही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में भी है। महाराष्ट्र की सरकार का अंतर्विरोध उसे डुबा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की अंतर्कलह से भूपेश बघेल भयभीत हैं तो यह डर अच्छा है। भूपेश बघेल इस डर में अगर राज्य की जनता के हित में सरकार चलाने लगें तो बेहतर है। भूपेश बघेल के दिमाग में भाजपा का डर छत्तीसगढ़ का भला करे तो यह भाजपा की जीत है। भाजपा चाहती है कि कांग्रेस सरकार जनता से किये गए वादे पूरे करे। लेकिन भूपेश बघेल तो भ्रष्टाचार का समर्थन करने अपनी सरकार को दिल्ली में डेरा डलवाये हुए हैं। न खुद को छत्तीसगढ़ की चिंता है और न ही वे अपने मंत्रियों को काम करने दे रहे। क्या जनता ने कांग्रेस को इसलिए अवसर दिया है कि छत्तीसगढ़ की फिक्र छोड़कर खानदान की चमचागिरी में लगे रहें? केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ में कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कांग्रेसी ही पर्याप्त हैं।

कांग्रेस के दिखाने और खाने के अलग अलग दांतः डा. रमन सिंह

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा बाहरी उम्मीदवार घोषित करने पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के खाने और दिखाने के अलग अलग दांत सामने आ गए हैं। छत्तीसगढियावाद को ओढ़ने और बिछाने का ढोंग करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति तो छत्तीसगढ़िया चाहिए लेकिन राज्यसभा में पंजाब, दिल्ली और बिहार चलेगा, यह दोहरा चरित्र ही कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस कहीं से भी लाकर छत्तीसगढ़ पर किसी को भी लाद दे, उसकी मर्जी लेकिन अब वह छत्तीसगढियावाद का तमाशा करना बंद कर दे। छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर एक बार देख लिया कि छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का ढिंढोरा पीटने वालों के कृत्यों में छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की क्या कीमत है, क्या अहमियत है और कांग्रेस कंपनी के मालिकों के हुक्म की क्या वजनदारी है। छत्तीसगढ़ की जनता से मिले समर्थन की छत्तीसगढ़ को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह जनता को अहसास नहीं था। जनता के आशीर्वाद को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दिल्ली दरबार को अर्पित कर दिया है। छत्तीसगढ़ की भावना का कोई मोल नहीं है। कांग्रेस के पास संख्याबल होने का यह मतलब नहीं है कि उसे छत्तीसगढ़ के आत्म सम्मान से खेलने का हक मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रवाद की वकालत करते हुए राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों को ललकारने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में सोनिया गांधी के सामने भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को सूली पर टांगकर कांग्रेस आलाकमान को कुर्सी की कीमत दी जा रही है। कांग्रेस अपने स्वाभिमान का जो करना है, शौक से करे लेकिन उसे छत्तीसगढ़ के जनादेश का ऐसा दुरुपयोग करने का परिणाम भोगने तैयार हो जाना चाहिए।

भूपेश को कुलपति छत्तीसगढ़िया चाहिए लेकिन राज्यसभा में पंजाब, दिल्ली, बिहार चलेगा

भाजपा आरटीआई सेल ने लगाया आरोप सरकारी रिकॉर्ड में ही बांट रही है सहायता राशि

भारतीय जनता पार्टी आर.टी.आई. सेल के प्रदेश संयोजक डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने आरोप लगाया है कि श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता में एक लाख रुपए योग्य हितग्राहियों को दिए जाने का प्रावधान है किन्तु सरकार से सूचना के अधिकारी से प्राप्त दस्तावेज में हितग्राहियों का आवेदन क्रमांक व लाभान्वित दिनांक भिन्न-भिन्न है किन्तु कई हितग्राहियों का लाभान्वित दिनांक अलग होने के उपरांत भी एक ही चेक नंबर से भुगतान दर्शाया गया है। यह कैसे संभव हो सकता है कि एक ही चेक अलग-अलग दिनांक में भिन्न-भिन्न हितग्राहियों को दिया गया हो। इस शासकीय अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि हितग्राहियों को सहायता राशि नहीं मिल रही है या सहायता राशि के लेनदेन में अनियमितता है या सरकार हितग्राहियों को सहायता राशि न देकर मात्र रिकॉर्ड में भुगतान दर्शा रही है। वास्तव में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस पूरे मामले में हितग्राहियों के परिवार को एक ही नंबर के चेक द्वारा भुगतान किया जाना दिखाया जा रहा है जो कई शंकाओं को जन्म देता है। इस पूरे मामले में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पर पर्दा डालने का काम भी प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।

देश सेवा से रोककर युवा पीढ़ी से गोबर बटोरवाना चाहते हैं मरकाम : केदार

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम राज्य के पढ़े लिखे युवाओं को देश की सेवा करने से रोककर गोबर बटोरने के काम पर लगाना चाहते हैं। वे चाहें तो युवा पीढ़ी को रोजगार और बेरोजगारी भत्ते का झांसा देने वाले अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए अपनों को गोबर रोजगार से जोड़ लें लेकिन उन्हें युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देने वाले सुझाव युवाओं को देने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वे अग्निपथ योजना का बहिष्कार करें। अग्निवीर बनने आवेदन न करें। ऐसी बेतुकी अपील करते हुए वे सेना का अपमान कर रहे हैं और कांग्रेस के देशविरोधी, सेनाविरोधी तथा युवा विरोधी चरित्र को ही उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस के आला बेरोजगार के भ्रष्टाचार के समर्थन में दिल्ली में ईडी दफ्तर के सामने नौटंकी करने वाले बिना रीढ़ के बेगैरत कांग्रेसी खुद तो राज्य के युवाओं को न रोजगार दे पा रहे और न ही वादे के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता दे रहे, बल्कि युवाओं का भविष्य चौपट करने की साजिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का युवा इनकी तरह स्वाभिमान बेच दे लेकिन हमारे युवा राष्ट्र भक्त हैं। कांग्रेस देश को कमजोर करना चाहती है। वह नहीं चाहती कि देश की सेना मजबूत हो। कांग्रेस नहीं चाहती कि युवा शक्ति देश की सेवा करे। कांग्रेस नहीं चाहती कि युवाओं को बेहतर भविष्य मिले। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि एक तरफ कानपुर में ऐलान हुआ है कि मुस्लिम युवा देश की सेवा के लिए आगे आकर अग्निवीर बनें , कई धर्म गुरुओ ने भी इस योजना मे शामिल होने की बात की है ।

छत्तीसगढ़, राज्यसभा और छत्तीसगढ़ियावाद

पंकज झा.

बात ज़रा सी पुरानी है। बात तब की है जब राज्यसभा जाने के लिए आपका संबंधित राज्य से होना ज़रूरी होता था। आपके लिए आवश्यक था कि आप उसी राज्य के निवासी हों जहां से आपको उच्च सदन जाना है। तो हुआ यह कि दुनिया के सबसे इमानदार घोषित सरदार मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस राज्यसभा भेजना चाह रही थी। लेकिन गुंजाइश बन रही थी असम से। फिर क्या था, झट 'ईमानदार साहब' को असम का निवासी बना दिया गया। वहां के सीएम तब होते थे हितेश्वर सैकिया, उन्होंने बकायदा सिंह साहब को अपना किरायेदार बनाया और 'असमिया' मनमोहन सिंह पहुंच गए ऊपरी सदन। प्रधानमंत्री रहते भी मनमोहन सिंह जी बतौर सैकिया के किरायेदार ही राज्यसभा में विराजमान रहे।

ये तो बात हुई सबसे इमानदार कांग्रेसी की, वह भी तब जब ऐसी बाध्यता थी। आज तो कम से कम ईमानदारी का दावा तो कोई कांग्रेसी नहीं करते और न ही बाध्यता है अब राज्यसभा में राज्य के निवासी होने की। ऐसे में कांग्रेस का आलाकमान ज़ाहिर है वही करता जो उसने किया। छत्तीसगढ़ से खाली हो रही दो राज्यसभा सीटें, जो विधायकों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस को ही जानी है, से कांग्रेस ने इस बार बिहार से रिश्ता रखने वाले रंजीत रंजन और उत्तर प्रदेश से आने वाले राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। श्रीमती रंजीत की बिहार में सबसे बड़ी उपलब्धित यही है कि वे उस बाहुबली राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव की पत्नी हैं जिन पर न जाने कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। कम्युनिस्ट विधायक के हत्या के मामले में तो पप्पू आजीवन कारावास के सजायाफ्ता भी हो गए थे जिन्हें उच्च न्यायालय से राहत मिली। अपहरण आदि के तमाम आरोपों की लम्बी फेहरिश्त है रंजन पति की। छत्तीसगढ़ से माननीय सांसद होने जा रहे दूसरे सज्जन राजीव शुक्ला भी परिचय के मुहताज नहीं हैं। उन्हें आप कांग्रेस का 'अमर सिंह' कह सकते हैं। बहरहाल, दिक्कत इस बात से नहीं है कि किसी एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य से अब उच्च सदन नहीं जा सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि लगातार तीन सांसद चुनने का मौक़ा कांग्रेस विधायकों को मिला है लेकिन उनमें से एक भी क्या छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यक्ति नहीं हो सकते थे? यह सवाल इसलिए और अधिक प्रासंगिक है क्योंकि विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति तक में सीएम भूपेश बघेल बड़ी ही बेशर्मी से न केवल जातिवादी कार्ड खेलते हैं, बल्कि उन्होंने कुलपति नियुक्ति के मुद्दे को हाल ही में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा बना दिया था। खुद को छत्तीसगढ़िया कहने वाले, बोरी बासी, भौरा बाटी आदि खेल कर स्थानीयता का राग अलापने वाले को इस हद तक छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्य करता देख कर खुद कांग्रेस के लोग भी सकते में होंगे ही।

दिक्कत इस बात से नहीं है कि किसी एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य से अब उच्च सदन नहीं जा सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि लगातार तीन सांसद चुनने का मौक़ा कांग्रेस विधायकों को मिला है लेकिन उनमें से एक भी क्या छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यक्ति नहीं हो सकते थे?

राजनीति निश्चित ही अवधारणाओं का खेल है। दिलचस्प यह है कि छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात करते हुए हमेशा बघेल उस भाजपा को कठघरे में खड़ा कर सुर्खियां भी बटोर लेते हैं, जिस भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है। लगभग पचास वर्ष तक अवसर मिलने के बावजूद कांग्रेस ने हर तरह से योग्य होते हुए भी छत्तीसगढ़ को कभी राज्य का दर्ज़ा नहीं दिया। प्रदेश के अपार खनिज एवं वन्य संसाधनों से देश भर के कांग्रेसी तृप्त होते रहे थे, जबकि प्रदेश के हिस्से में आती रही थी गरीबी, भुखमरी और शोषण। समूची दुनिया में जिस आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने पलायन, शोषण और पिछडापन का प्रतीक बना दिया था, उसी छत्तीसगढ़ के बारें में डींगें हांकते वे उस भाजपा पर सवाल उठाते हैं जिसने न केवल प्रदेश की समृद्धि को पहचान दी बल्कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का भी दर्ज़ा दिया।

महज़ नमक के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा देने वाले आदिवासी क्षेत्र के गरीबों सहित समूचे प्रदेश के ज़रूरतमंदों को नमक समेत सम्मान से भोजन, चावल, शिक्षा, सड़क आदि ज़रूरतों को पूरा करने में जी-जान से कोशिश भाजपा ने की। उस भाजपा ने जैसा कि पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह कहते हैं –'जिसने लगातार अवसर मिलने के बावजूद कभी भी यहां से किसी गैर-छत्तीसगढ़िया को राज्यसभा नहीं भेजा। ' खुद भूपेश बघेल के घर पर 'छत्तीसगढ़' लिखने वाली भाजपा इस अस्मिता की विरोधी करार दे दी गयी, जबकि दस जनपथ के आदेश पर यहां के संसाधन से देश भर में चुनाव लड़ने वाले, प्रदेश के लोगों का हक़ छीन कर दिल्ली

पहुंचा देने वाले बघेल 'छत्तीसगढ़िया' हो गए। क्या कहा जाए इस विडंबना को!

भाजपा के उलट कांग्रेस को लगभग जब भी मौक़ा मिला, उसने अधिकांशतः यहां की सीट से आलाकमान को एक सेवक की तरह खुश करने का काम किया है। इससे पहले के. टी. एस. तुलसी और मोहसिना किदवई जैसे ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा गया, जिन्होंने सांसद बनने से पहले छत्तीसगढ़ को केवल नक़्शे पर देखा हुआ था। तुलसी का मामला तो और रोचक है। वे तो राज्यसभा में हुई जीत का प्रमाण पत्र तक लेने छत्तीसगढ़ आने की ज़हमत नहीं उठायी। तुलसी को उनके घर जा कर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री सांसदी का प्रमाण पत्र दे आये जिसे लेकर वे छत्तीसगढ़ियों को चिढ़ाते हुए सदन में पंजाबी में शपथ ली थी। क्या कहा जाय इसे।

ऐसे हालात में प्रदेश में भाजपा को क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है संख्या बल के अनुसार उसके पास फिलहाल छग विधानसभा में कोई अवसर नहीं है। लेकिन फिर भी भाजपा को ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे प्रतीकात्मक ही सही लेकिन विरोध दर्ज कराया जा सके। छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेने के बाद कांग्रेस ने सबसे अधिक 'भरोसे का संकट' पैदा किया है। उसने जो भी कहा ठीक उसका उलटा करने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। जैसे शराबबंदी का वादा कर शराब की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी। किसानों को मंडी टैक्स माफ़ करने कला वादा कर उसे डेढ़ गुना अधिक बढ़ा दिया। बेरोजगारी भत्ता देने का लिखित वादा कर साफ़ ही मुकर गयी कि ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। और अब ये कि स्थानीयता का ढोल पीट-पीट करइस बहाने प्रदेश में उग्र ताकतों को संरक्षण तक देकर अपनी राजनीति चमकाई, खुद राम-राम करते रहे जबकि पिता ने श्रीराम के बारे में अनर्गल बयानबाजी और अपशब्द कहते रहने का कीर्तिमान अपने नाम किया, और राज्यसभा से लगातार तीन सांसद ऐसे बनाए जिनका छत्तीसगढ़ से उतना ही लेना देना रहा है जितना कांग्रेस का 'ईमान' से लेना देना होता है।

भाजपा के उलट कांग्रेस को लगभग जब भी मौक़ा मिला, उसने अधिकांशतः यहां की सीट से आलाकमान को एक सेवक की तरह खुश करने का काम किया है। इससे पहले के. टी. एस. तुलसी और मोहसिना किदवई जैसे ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा गया, जिन्होंने सांसद बनने से पहले छत्तीसगढ़ को केवल नक़्शे पर देखा हुआ था।

दिलचस्प यह भी है कि सत्ता वाले दोनों राज्य में कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं के साथ ऐसा ही चमत्कार किया है। राजस्थान से जिस रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है, उनमें से किसी का भी रिश्ता राजस्थान से नहीं है। हालांकि वहां कम से कम एक कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने सवाल उठाने की हिमाकत की और कहा कि – 'पार्टी को बताना होगा कि राजस्थान से किसी को भी उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया।' दुःख की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 71 कांग्रेस विधायकों में से किसी में इतना तक कह पाने का भी साहस नहीं है। यहां तक कि उस स्वाथ्य मंत्री टी. एस. सिंहदेव भी इस मामले में भी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर पाए जिन्हें ढाई-ढाई साल के फार्मूले का झूठा आश्वासन देकर पहले ही ठगा जा चुका है। जिनके पास खोने को फ़िलहाल कुछ अधिक नहीं है।

खैर, देखना दिलचस्प होगा कि खुद भी कुछ पीढी पहले बाहर से आकर अंचल में धंधा जमा चुके बघेल परिवार विश्वसनीयता के इस संकट के साथ आगे किस तरह अपनी राजनीति को अंजाम देता है। छत्तीसगढ़ से कर रहे ऐसी गुस्ताखियों का जवाब यहां की जनता उन्हें कैसे देती है। फिलहाल तो तीन-तीन बाहरी सांसदों को नियुक्त कर स्थानीय अस्मिता का राग अलापते मुख्यमंत्री के दोमूहापन को एकटक देखते रहने के अलावा छत्तीसगढ़ के लोगों, कांग्रेसियों के पास और चारा ही क्या है? प्रदेश के कांग्रेसियों की तपस्या में निश्चय ही पवन खेड़ा, नगमा या आचार्य प्रमोद कृष्णम, आज़ाद जैसी कुछ कमी रह गयी होगी। नारे तो खैर फिर भी बघेल लगायेंगे ही- सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। ●●●

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रायपुर प्रवास के दौरान महिला मोर्चा की बहनों को सम्बोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. रमन सिंह भी उपस्थित थे।

निवेदन

दीप कमल से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं या Watsapp कर सकते हैं. फोन से भी जानकारी दे सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं. इसके अलावा आपके क्षेत्र में संगठन से संबंधित कोई गतिविधि या पत्रिका में प्रकाशन योग्य कोई समाचार हो, तो उसे भी निम्नलिखित माध्यमों से भेजने का आग्रह है।

कार्यकारी संपादक, दीप कमल, प्रदेश भाजपा कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर
डूमरतराई, रायपुर. (छग), फोन : 0771-2233500, Watsaapp 9425507006, E mail – jay7feb@gmail.com

...नैनन के जल से पग धोये।